सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 272, नई दिल्ली । बुधवार, 11 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

समुद्र में चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, समुद्र अपनी शांति कभी नहीं छोड़ता

03 कब तक दी जाएंगी मुफ्त चीजें', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल

06 शादियों और पार्टियों में दिखावा

08 क्या सियासी दलों पर भी लागू होगा पीओएसएच एक्ट?

चुनाव से पहले दिल्ली सरकार का डीटीसी के ड्राइवरों-कंडक्टरों को तोहफा, बढ़ेगा वेतन

दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने चुनाव के पहले साफ कहा कि डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए ड्राइवरों और कंडक्टरों की सैलरी बढ़ाई जाएगी. साथ ही इनको अपने घरों के नजदीक ही ड्यूटी दी जाएगी.

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने कहा कि डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों की सभी मांगों के मान लिया जाएगा. उनकी तनख्वाह को बढ़ाने के साथ ही इन सभी की ड्यूटी उनके घरों के पास मौजूद डिपो में लगाई जाएगी. एक प्रेस कांफ्रेंस में सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में डीटीसी बसें दिल्ली की लाइफलाइन हैं. दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें डीटीसी बसें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं. डीटीसी बसों से बच्चे स्कूल जाते है और लोग आफिस जाते हैं. डीटीसी बसों से कई हजार लोग रोजाना सफर करते हैं. उन्होंने बताया कि डीटीसी में 4500 कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवर और 17850 कॉन्ट्रैक्ट वाले कन्डक्टर हैं.

दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि कुछ दिन पहले ये सब हड़ताल पर गए थे. सबसे पहले तो उनका धन्यवाद जिन्होंने हमारी बात करने के बाद अपनी हड़ताल खत्म की. अब उनकी मांगों को हमने मान लिया है. सबसे पहली मांग सरोजिनी नगर पिंक डिपो में जो महिलाएं काम करती थीं, उन्हें उनके पहले वाले डिपो पर ही भेज दिया जाएगा. आतिशी ने कहा कि दूसरा सभी कंडक्टर और ड्राइवरों की मांग थी कि उनकी ड्यूटी उनके घर से काफी दूर लगाई जाती है.

ड्यूटी के लिए बनेगी वेबसाइट

सीएम आतिशी ने कहा कि अब हम एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे. जिसमे कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवर और कन्डक्टर आवेदन करेंगे. उसमें वो अपने घर का पता लिखेंगे और उसके हिसाब से उन्हें उनके घर के पास वाले डिपो में जगह दी जाएगी. जो डीटीसी ड्राइवर प्रोमोट हो रहे हैं, उनकी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवर को नौकरी दी जाएगी. सभी कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक बस चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी.

कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवरों को कन्डक्टरों का वेतन बढ़ेगा दिल्ली की सीएम आतिशी ने बताया कि अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवरों को कन्डक्टरों को 843 रुपये रोजाना और 21918 रुपये वेतन अभी मिलता है. हमने एक प्रस्ताव आज भेजा है जिसमे कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवर और कन्डक्टर की सैलरी को बढ़ाया जाएगा. जल्दी ही ये प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट वाले कन्डक्टर की सैलरी जल्दी ही 29250 हो जाएगी. जबकि कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवर की सैलेरी जल्द ही 32918 रुपये महीने होगी. इससे दिल्ली सरकार पर 222 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालों की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, गडकरी ने बताया-क्या है उनका प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है या लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्रीय मंत्री नतिनि गडकरी के नए प्लान से आपकी बल्ले-बल्ले होने वाली है. गडकरी ने एक न्यूज चैनल की तरफ से आयोजति कार्यक्रम में मुंबई में कहा कि सरकार दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाइवे बनाने का प्लान कर रही है. इससे पहले भी वह अलग-अलग कार्यक्रम में दल्लिी-जयपुर इलेक्ट्रकि हाइवे का जक्रि कर चुके हैं.

इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने पर काम कयिा जा रहा इलेक्ट्रिक हाईवे सड़कों या हाईवे का एक नेटवर्क है जो इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए विशेष रूप से डजिाइन कयि गए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होता है. ये हाईवे आमतौर पर रूट के साथ चार्जिंग सिस्टम की सुविधा देते हैं ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों की लंबी दूरी की यात्रा ज्यादा सुविधाजनक हो सके. पछिले दनिों ईटी में प्रकाशति खबर में भी दावा कयिा गया था कि सरकार इंटरसिटी पब्लकि ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रीफकिेशन के जरयि ईंधन की खपत और वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के प्रयास के तहत गोल्डन क्वाड्रलिटर के साथ इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने के प्लान पर काम कर रही है.

6,000 किमी इलेक्ट्रकि हाइवे बनाने का टारगेट केंद्र सरकार का टारगेट 6,000 किमी इलेक्ट्रकि हाइवे बनाने का है. प्रोजेक्ट को अगले सात साल में शुरू कयिा जाना है, जसिका टारगेट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाना और देशभर में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को सुविधाजनक बनाना है. ई-हाईवे में ग्रीन एनर्जी से चलने वाले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा होगी. यह पहल 2030 - पीएम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा कार्यक्रम का हिस्सा है.

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहति करने का प्लान इलेक्ट्रिक हाईवे का डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री के साथ-साथ होने की संभावना है, जिससे भारत में ईवी के लिए इकोसस्टिम की स्थापना में तेजी आएगी. नए ई-हाईवे से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को गति मिलने की उम्मीद है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रोजाना के सफर के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

पिछले साल 83,000 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पिछले साल इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री बढ़कर 83,000 यूनिट तक पहुंच गई. हालांकि इनकी बक्रिी का टारगेट एक लाख का रखा गया था. कई पहली बार खरीदारों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने प्राथमिक परिवहन साधन के रूप में चुनने में हिचकिचाहट दिखाई है, मुख्य रूप से रेंज और देश में अपर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंताओं के कारण. नतीजतन, उपभोक्ताओं ने ईवी को मुख्य वाहन के बजाय द्वितीयक या तृतीयक विकल्प के रूप में देखा है.

गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार देश को बॉयो फ्यूल के मामले में दुनिया में शीर्ष पर बनाने का भी प्लान कर रही है. साथ ही उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार नागपुर में एक इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिससे टिकट की कीमतें 30 प्रतिशत तक कम होने की है।

आप के बाद दिल्ली में अब बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक, ऑटोवालों को मिल गई एक और बड़ी खुशखबरी

भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से ऑटो चालकों ने मुलाकात कर समस्याएं हल करने की मांग की।

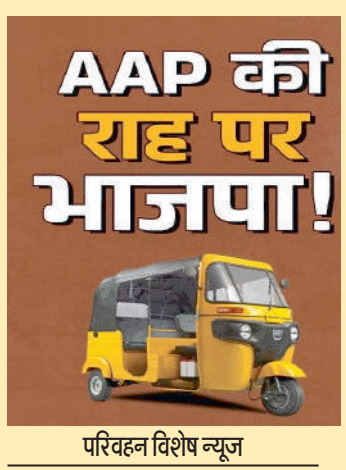

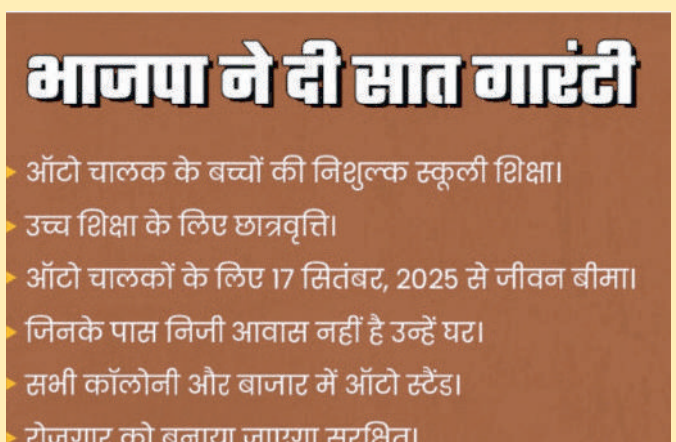

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके जवाब में भाजपा ने ऑटो चालकों को सात गारंटी देने का वादा किया है। भाजपा के अनुसार उनके शासन में ऑटो चालकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा जीवन बीमा आदि जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की।

जिसके बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राजधानी में भाजपा की सरकार बनाने के लिए हम ऑटोवालों को सात गारंटियां देंगे। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से ऑटो चालकों ने मुलाकात कर समस्याएं हल करने की मांग की।

कोरोना महामारी के समय भी सरकार ने नहीं की कोई मदद-सचदेवा

सचदेवा ने कहा, विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर एक बार फिर से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय भी सरकार ने ऑटो चालकों की सहायता नहीं की।

उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर ऑटो चालकों की समस्याएं दूर करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की सात गारंटी दी। प्रत्येक लाइसेंस वाले ऑटो चालक के बच्चों की निशुल्क स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति।

ऑटो चालकों के लिए 17 सितंबर, 2025 से जीवन बीमा, जिनके पास निजी आवास नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी कॉलोनी व बाजार में ऑटो स्टैंड, उनके रोजगार को सुरक्षित बनाने, ई - ऑटो रिक्शा लेने वाले को दो वर्ष तक प्रति माह तक रीचार्ज सहयोग राशि देने का आश्वासन दिया। सभी ऑटो फिटनेस सेंटर में कमेटी बनाकर भ्रष्टाचार रोकने का आश्वासन दिया। कमेटी को दो ऑटो चालक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

केजरीवाल ने किए पांच बड़े एलान

जैसे-जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। ठीक वैसे-वैसे सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी है। इसी कड़ी में मंगलवार को सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली के सभी ऑटोवालों के लिए पांच बड़ी घोषनाएं की हैं।

जिसमें उन्होंने कहा कि हर ऑटोवाले का 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करेंगे और इसके अलावा 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा। इसके बाद उन्होंने अगली गारंटी में कहा कि हर ऑटोवाले को बेटी की शादी के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। ऑटोवालों को वर्दी के लिए वर्दी के लिए साल में दो बार 2500 रुपये दिए जाएंगे। बच्चों की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।

सीडीवी को बस मार्शल के तौर पर लगाने के मुद्दे पर फिर गरमाया माहौल, आमने सामने एलजी और दिल्ली सरकार

पारिवहन विशेष न्यूज

बस मार्शलों के तौर पर सिविल डिफेंस वालंटियर्स की नियुक्ति को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। आप ने आरोप लगाया भाजपा पिछले एक साल से सीडीवी को गुमराह कर रही है और उन्हें बस मार्शल के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। राजनिवास का कहना है दिल्ली सरकार ने कभी भी सीडीवी को बस मार्शल के तौर पर लगाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है।

नई दिल्ली। सीडीवी (सिविल डिफेंस वालंटियर्स) को बस मार्शल के तौर पर लगाने के मुद्दे पर फिर माहौल मंगलवार को फिर माहौल गरमा गया। आप ने आरोप लगाया कि पिछले एक साल से भाजपा सीडीवी को गुमराह कर रही है और उन्हें बस मार्शल नहीं लगाया गया। उधर राजनिवास ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने कभी भी सीडीवी को बस मार्शल लगाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है।

आप ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के 10 हजार से भी अधिक नौजवान बेटे बेटियां जो डीटीसी की बसों में बस मार्शल के रूप में कार्य कर रहे थे, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने का काम कर रहे थे और इस बहाने से उन सभी के घरों के चूल्हे भी जल रहे थे, ऐसे 10 हजार दिल्ली के नौजवान बेटे बेटियों को एलजी ने एक झटके में नौकरी से निकाल दिया।

आप ने आरोप लगाया है कि पहले एक षड्यंत्र के तहत उन सभी का वेतन रोका गया और बाद में सभी को नौकरी से निकाल दिया गया। आप ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी की अगवाई में सभी कैबिनेट मंत्रियों ने एक नोट पास किया और उपराज्यपाल को भिजवाया हुआ है, परंतु उपराज्यपाल ने दिल्ली के बस मार्शलों के हित में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है।

इस मुद्दे पर शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता भी की। उन्होंने भाजपा और एलजी पर सीवीडी के मुद्दे पर हमले किए। उन्होंने कहा कि इन लोगों का दोहरा चरित्र सीडीवी देख रहे हैं।

उधर राजनिवास ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने कभी भी सीडीवी को बस मार्शल के तौर पर लगाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। राजनिवास के अनुसार उन्होंने केवल मौखिक रूप से सिविल डिफेंस वालंटियर्स को बस मार्शल घोषित करके लोगों को मूर्ख बनाया।

राजनिवास ने कहा कि यहां तक कि पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल की सिफारिश पर इन्हें भी समाप्त कर दिया गया था। उनकी सिफारिशों पर सहमति जताते हुए भी एलजी ने जल्द से जल्द उनके पुनर्नियुक्ति के लिए वैकल्पिक योजना बनाने के लिए कहा था। तब से आप ने केवल दिखावा किया है और सिविल डिफेंस वालंटियर्स को मूर्ख बनाया है।

राजनिवास ने कहा है कि अभी भी उन्होंने बस मार्शलों को फिर से नियुक्त करने के लिए कोई योजना बनाने और कैबिनेट का फैसला लेने के बजाय एलजी को एक पत्र लिखा है। एलजी ने आप, आतिशी और केजरीवाल की आलोचना की है और उनके इस ढोंग को उजागर किया है।

एलजी ने फिर से उनसे सीवीडी को बस मार्शल के रूप में नियुक्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाकर उनके वेतन के लिए बजट प्रदान करने और कैबिनेट का फैसला लेने के लिए कहा है।

राजधानी में क्यों हो रहे इतने हादसे? बड़ी वजह आई सामने; वाहन चलाते समय जरूर ध्यान रखें ये नियम

परिवहन विशेष न्यूज

राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही है। राजधानी में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह भी सामने आई है। बताया गया कि हाईवे पर संकेतक नहीं होने की वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर रोड पर संकेतक होते हैं तो चालक पहले ही अलर्ट हो जाता है।

नई दिल्ली। राजधानी में बिना संकेतकों वाली सड़कें और यातायात नियमों का उल्लंघन लोगों के जीवन पर भारी पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त सड़कें, संकेतकों के अभाव से दिल्ली की सड़कें और ज्यादा असुरक्षित होती जा रही हैं। वहीं, दुर्घटना से बचाने वाले छोटे-छोटे मानकों का उल्लंघन भी बड़े-बड़े खतरे का कारण बन रहे हैं। इसमें सड़कों पर रिफलेक्टर, डार्क स्पाट, थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग, वाहनों में बैक लाइट और आइने का अभाव सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं।

परिवहन विभाग भी इसे लेकर गंभीर नहीं

लोगों के साथ ही यातायात पुलिस और परिवहन विभाग भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। किसी भी शहर में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए संकेतकों की अहम भूमिका होती है। सफर करने के दौरान संकेतक हमें पहले से ही बता देते हैं कि आगे स्कूल है, अस्पताल है, सड़क पर कोई खतरनाक मोड़ है, क्रासिंग है। इससे बड़ा लाभ यह होता है कि चालक सतर्क हो जाता है और वाहन की गति उसी हिसाब से नियंत्रित करते हुए खुद को सुरक्षित करता है। वहीं, मोटर वाहन एक्ट में भी इसे लेकर निर्देश है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। सड़कों की लेन पर रिफलेक्टर भी नहीं हैं, जिससे अक्सर लोग रात में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। शायद यही कारण है कि दिल्ली में दिन की अपेक्षा रात में दुर्घटनाएं अधिक होती हैं।

चेतावनी देने वाले संकेतकों की कमी

बताया गया कि सड़कों पर गति कम करने की चेतावनी देने वाले संकेतकों की कमी है। उचित रोशनी और रोड ब्लिंकर्स, थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग, रिफ्लेक्टिव बोलार्ड्स कई जगह नजर नहीं आते हैं। खासकर सर्दियों में जब कोहरा होता है तो ये लाइटें सुरक्षित यातायात के लिए काफी सहायक होती हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वाहनों की संख्या के हिसाब से ढांचागत विकास अपर्याप्त है और यातायात का घनत्व बहुत अधिक है। पैदल चलने वालों के लिए सुविधाओं की कमी के साथ यातायात निमयों को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है।

कई हिस्सों में यातायात नियमों का उल्लंघन ज्यादा

लुटियंस दिल्ली को छोड़ दें तो दिल्ली के अन्य हिस्से में यातायात नियमों का उल्लंघन ज्यादा है और सड़कों पर डार्क स्पॉट, रिफ्लेक्टर जैसी कमियां हर तरफ हैं। चूंकि दिल्ली में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं रात में होती हैं, ऐसे में यह और भी आवश्यक है कि छोटी दिखने वाली समस्या लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है।

चुकंदर से बनाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद ऐसा कि बार-बार करेगा खाने का दिल

आप चुकंदर के कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिसको खाकर कोई भी इन डिशेज का दीवाना हो जाएगा। फिर चाहे चुकंदर की टिक्की हो, चुकंदर का हलवा हो या फिर चुकंदर का पराठा हो।

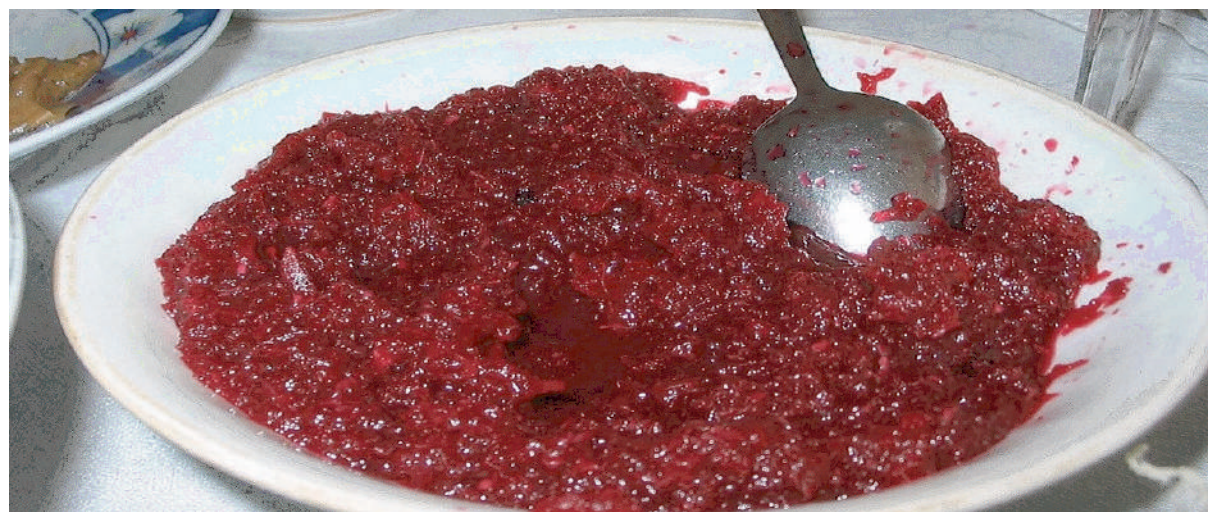

चुकंदर हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह एक हेल्दी और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसके सेवन से हमारी शरीर को कई फायदे मिलते हैं। रोजाना चुकंदर का सेवन करने से हमारे शरीर को फाइबर, आयरन और कई तरह के एंटी-ऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। हालांकि कई लोगों को चुकंदर का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में अगर आपको भी चुकंदर का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

क्योंकि आप इसका ऐसा स्वाद बना सकते हैं, जो हर किसी को आसानी से पसंद आएगा। बता दें कि आप चुकंदर के कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिसको खाकर कोई भी इन डिशेज का दीवाना हो जाएगा। फिर चाहे चुकंदर की टिक्की हो, चुकंदर का हलवा हो या फिर चुकंदर का पराठा हो। यह रेसिपीज चुकंदर के गुणों के साथ-साथ स्वाद का भी भरपूर ख्याल रखती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको चुकंदर की कुछ रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगी।

चुकंदर का जैम

बता दें कि चुकंदर का जैम बनाना बेस्ट ऑप्शन है। इसका स्वाद भी अच्छा होता है और यह स्वादिष्ट भी होता है। वहीं चुकंदर जैम बनाने में बहुत कम समय लगता है। साथ ही यह बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को पसंद आता है।

सामग्री

चुकंदर- 2
इलायची पाउडर- आधा चम्मच
चीनी- 1 कप
नींबू का रस- 1 चम्मच
पानी- आधा कप

ऐसे बनाएं चुकंदर जैम

चुकंदर जैम बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छे से धो लें। फिर चुकंदर को कद्दूकस कर लें या फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

इसके बाद एक पैन में आधा कप पानी डालकर कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डालें।

अब चुकंदर को हल्दी आंच पर तब तक उबालें जब तक वह नरम न हो जाए।

जब उबालने पर चुकंदर का पानी सूख जाए, तो उसको मिक्सी में डालकर प्यूरी बना लें।

अब प्यूरी को पैन में निकालकर उसमें चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करें।

इस प्यूरी को हल्की आंच पर पकाएं और जब कुछ देर बाद प्यूरी से चिपचिपाहट आने लगे, तो इसका मतलब है कि जैम पकने लगा है।

जब जैम गाढ़ा हो जाए, तो इसमें नींबू का पस और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। जैम तैयार होने के बाद छोटी प्लेट में जैम की कुछ बूंदे डालें।

अगर प्लेट में जैम आसानी से फैल रहा है, तो इसका मतलब है कि यह बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अगर यह कटा हुआ दिखे, तो इसको कुछ देर और पकने दें।

पकने के बाद जैम को पैन से निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें और इस्तेमाल में लाएं।

चुकंदर फ्राइज

अगर आप स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, तो चुकंदर से फ्राइज तैयार कर सकते हैं। हालांकि, इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान रखा जाए तो यकीनन एक अच्छे फ्राइज तैयार किए जा सकते हैं।

सामग्री

चुकंदर- 2
जीरा पाउडर- आधा चम्मच
हल्दी पाउडर- आधा चम्मच
नमक- स्वादानुसार)
ताजा धनिया- 1-2 बड़े चम्मच
नींबू का रस- 1 चम्मच
आलू का आटा- 2 बड़े चम्मच
कॉर्नफ्लोर- 1 चम्मच
लाल मिर्च पाउडर- आधा चम्मच
तेल- तलने के लिए

ऐसे बनाएं चुकंदर फ्राइज

ऊपर बताई गई सामग्रियों को तैयार करके रखें और फिर चुकंदर को धोकर छील लें। अब चुकंदर को पतले स्ट्रिप्स में काट लें।

आप चाहें तो चुकंदर को काटने के लिए कटिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे कि फ्राइज एक समान आकार की हों।

अब पैन में पानी उबालें और उसमें कटी चुकंदर की स्ट्रिप्स डालें। चुकंदर को 3-4 मिनट तक उबलने दें, जिससे कि वह नरम हो जाएं लेकिन पूरी तरह से पकें नहीं।

इसके बाद चुकंदर को छानकर ठंडे पानी में डालें, जिससे कि यह जरूरत से ज्यादा न गलें। फिर चुकंदर की स्ट्रिप्स को एक साफ कपड़े पर रखकर अच्छे से सुखाएं।

सुखाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि स्ट्रिप्स में एक्स्ट्रा पानी न हो। अब एक बाउल में कॉर्नफ्लोर, आलू का आटा, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालें।

फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक गाढ़ा बैटर तैयार करें। आप चाहें तो इसमें धनिया की पत्ती और नींबू का रस भी मिला सकते हैं।

चुकंदर स्ट्रिप्स को तैयार बैटर में डुबोकर अच्छे से कोट करें, जिससे कि स्ट्रिप्स बैटर अच्छे से कवर हो जाएं।

इसके बाद एक कड़ाही में तेल गर्म करें और फिर चुकंदर की स्ट्रिप्स को धीरे-धीरे तेल में डालें। फ्राइज को मीडियम आंच में कुरकुरा होने तक पकने दें।

तले हुए फ्राइज को किचन टॉवल में निकालकर एक्सेस तेल सोखने दें। अब आप इन्हें हरी चटनी या सॉस के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

चुकंदर का रायता

चुकंदर का रायता स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आप चाहें तो इसका रोजाना सेवन कर सकती हैं। उससे पेट को भी ठंडक मिलेगी और चुकंदर के पोषक तत्व इसको पौष्टिक भी बना देते हैं।

सामग्री

चुकंदर- 1
दही- 1 कप
जीरा पाउडर- 1 चम्मच
लाल मिर्च पाउडर- 1 चम्मच
हरा धनिया- 1 कप
नींबू का रस- 1 चम्मच
नमक- स्वादानुसार

ऐसे बनाएं चुकंदर का रायता

चुकंदर का रायता बनाने के लिए चुकंदर को अच्छे से धो लें और छील दें। अब इसको कद्दूकस कर लें और पैन में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डालें।

इसके बाद चुकंदर को 3-4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने दें, जिससे कि यह नरम हो जाए। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दें।

अब बाउल में दही निकालकर उसको अच्छे से फेंट लें और फेंटे हुए दही में काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डालें।

फिर ठंडा किया हुआ चुकंदर दही में डालकर अच्छे से मिक्स करें।

अगर आप थोड़ा खट्टा रायता खाना पसंद करते हैं, तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। इस तरह से चुकंदर का रायता बनकर तैयार हो जाएगा।

आप ऊपर से हरा धनिया डालकर इसे सर्व कर सकते हैं।

न्यू ईयर पर बनाएं घूमने का प्लान, आज ही मुंबई से बुक करें ये 3 टूर पैकेज

साल का आखिरी महीना दिसंबर भी जल्द खत्म हो जाएगा। अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप बजट में बिना किसी झंझट के मस्त यात्रा का एन्जॉय कर सकते हैं।

अगर आप भी न्यू ईयर पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप इन टूरिस्ट प्लेसिस पर जरुर घूमने जाएं। नववर्ष के दौरान ट्रैवल प्लेसिस पर भीड़ ज्याजा देखने को मिलती है। कई बार तो होटल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। नया साल के समय होटल भी काफी महंगे हो जाते हैं। टूर पैकेज से यात्रा प्लान करने से कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। आइए आपको बताते हैं इन टूर पैकेज के बारे में-

भुज टूर पैकेज

- इस टूर पैकेज की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से हो रही है।
- पहले यह देखले कि पैकेज में क्या सुविधा मिल रही हैं, तभी टिकट बुक करें।
- बता दें कि, पैकेज 4 रात और 5 दिनों का है। इसके बाद आप हर बुधवार टिकट बुक कर सकते हैं।
- पैकेज मे ट्रेन यात्रा करने का मौका मिलेगा।
- अकेले यात्रा करने पर पैकेज फीस 34399 रुपये है।
- वहीं, 2 लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति पैकेज फीस 21399 रुपये है।
- 3 लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति पैकेज फीस 18099 रुपये है। वही, बच्चों के लिए पैकेज फीस 11699 रुपये है।

तिरुपति और कोल्हापुर टूर पैकेज

- यह पैकेज 5 रात और 6 दिनों का है।
- इस पैकेज की टिकट आप कल्याण, लोकमान्य तिलक, मुंबई, पुणे, सोलापुर और ठाणे से बुक करें।
- अकेले यात्रा करने पर इस पैकेज की फीस 19375 रुपये है।
- पैकेज फीस- 2 लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति पैकेज फीस 15575 रुपये है।
- तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति पैकेज फीस 15175 रुपये है।
- बच्चों के लिए पैकेज फीस 13875 रुपये है।

चंडीगढ़, मनाली और शिमला टूर पैकेज

- इस पैकेज की शुरुआत 12 दिसंबर से हो रही है। इसके बाद आप हर गुरुवार टिकट बुक कर पाएंगे।
- यह पैकेज 7 रात और 8 दिनों का है।
- अकेले यात्रा करने पर पैकेज फीस 48100 रुपये है।
- 2 लोगों के लिए प्रति व्यक्ति पैकेज फीस 35800 रुपये है।
- 3 लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति पैकेज फीस 34000 रुपये है। वहीं, बच्चों के लिए पैकेज फीस 29300 रुपये है।

आयुर्वेद में खाने-पीने के होते हैं बड़े नियम, कब-किस समय भोजन करना चाहिए?

आयुर्वेद में हर चीज को लेकर टाइमिंग बताई गई है, आपका रहन-सहन हर तरीका के बारे में पता चलता है। आयुर्वेद में बताया गया कि आपको किस समय और कब खाना चाहिए। अगर आप गलत समय पर खाना खाते हैं तो आपको 100 प्रकार की बीमारियां हो सकती है।

संसार में सूर्य काफी महत्वपूर्ण है और सनातन धर्म में भी सूर्य काफी विशेष माना गया है। अगर एक दिन सूरज नहीं उगेगा तो संसार नष्ट हो सकता है। हालांकि, आप नहीं जानते होंगे कि खाना खाने से पहले भी सूरज को देखना काफी जरुरी है। खाने से लेकर पानी पीने तक आयुर्वेद में कई नियम बताए गए हैं। इस लेख में हम आपको इस रुल के बारे में बताने जा रहे हैं।

खाना खाने का बेस्ट टाइम

बता दें कि खाना खाने का टाइम और सूरज के बीच गहरा संबंध है। एक्सपर्ट के मुताबिक, सूर्यास्त के बाद डिनर और सूर्योदय से पहले ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। खाने-पीने के इस नियम को जरुर फॉलो करें।

सूरज के अनुसार चलता है शरीर

हमारा शरीर वात, पित्त और कफ दोष चलाते हैं, वैसे ही संसार को सूर्य, चंद्रमा और वायु चलाते हैं। इन्हीं के हिसाब से हमारे दोष चलते हैं और सूर्य के अनुसार ही हमारी बॉडी चलती है।

सूर्यास्त के बाद भोजन करना जहर होता है

जो लोग सूर्यास्त के बाद भी खाना खाते हैं, तो उनका भोजन पचता नहीं है। इस वजह से वो अमा बनाएगा, अमा का मतलब विष यानी के जहर। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में बताया है, जो खाना अपच रह जाता है, उसके वजह से शरीर को 100 बीमारियां हो सकती हैं।

बढ़ जाएगा यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल

एक्सपर्ट की माने तो, अपत भोजन के कारण कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है। संसार में जितने भी टॉक्सिन व अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो बढ़ते हैं। इसके पीछे अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट भी हो सकती है।

किचन की जिद्दी से जिद्दी दाग वाली जगहें होगी साफ, बेकिंग सोडा का करें यूज, सादा पानी से कुछ नहीं होगा

किचन में लगी हुई गंदगी सादे पानी से साफ तो नहीं होने वाली है। अगर आपकी किचन की कुछ जगहें हद से ज्यादा गंदी हैं, तो आपको इनको जरुर साफ करें। इन जगहों को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं।

अगर घर की किचन में गदगी होगी तो यह देखने में तो खराब लगती ही और सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। किचन की साफ-सफाई का खास ख्याल रखना भी जरुरी है। अगर आप भी अपनी किचन को सादे पानी से साफ करते हैं, तो यह करना बंद कर दीजिए। किचन की साफ-सफाई के लिए सादा पानी की जरुरत नहीं है। किचन में लगे हुए तेल के छींटे, मसालों के दाग और चिकनाई हटाने के लिए आप बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करें।

गैस चूल्हा और बर्नर की सफाई

किचन में सबसे ज्यादा गंदगी गैस चूल्हे पर देखने को मिलती है। तेल की चिकनाई और मसालों के दाग अक्सर जम जाते हैं। सादा पानी से उन्हें साफ करने से सफाई ढंग से नहीं होती है। इसलिए आप साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें।

कैसे करें साफ

- सबसे पहले आप एक कटोरी में बेकिंग सोडा और थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं।
- इस पेस्ट को चूल्हे और बर्नर पर लगाएं।
- फिर आपको इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें।
- इसके बाद आप स्क्रब करके गीले कपड़े से पोंछ लें।

सिंक और नल कैसे साफ करें

- इसके लिए आप बेकिंग सोडा को सीधे सिंक और नल पर छिड़कें।
- फिर आप पुराने टूथब्रश की सहायता से स्क्रब करें।
- इसके बाद आप पानी से धो लें और साफ कपड़े से सुखा लें।

किचन स्लैब की सफाई

- बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर एक घोल बनाएं।
- इसे स्लैब पर स्प्रे करें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें।
- फिर आप गीले कपड़े से पोछ लें। इससे केवल दाग हटेंगे और साथ ही स्लैब की सतह चमकदार हो जाएगी।

माइक्रोवेव और ओवन की सफाई

- इसके लिए आपको बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर दाग वाली जगहों पर लगाएं।
- 10-15 मिनट बाद आप गीले स्पंज से पोंछ लें।
- ग्रीस और बदबू दोनों ही खत्म हो जाएंगे।

फ्रिज के अंदर की सफाई

- एक बाउल में पानी और बेकिंग सोडा मिलाएं।
- इसके बाद फ्रिज की सतह पर इसे कपड़े की मदद से लगाएं और पोंछ दें।
- फ्रिज साफ हो जाएगा और ताजगी सा महसूस भी होगा।

इन आसान तरीकों से ढूंढें स्मार्टफोन में वायरस, इन स्टेप्स को करें फॉलो

स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे ही वायरस और मालवेयर वाले ऐप्स का खतरा भी बढ़ा है। ये खतरनाक ऐप्स ने केवल आपके फोन की गति को धीमा कर सकते हैं, बल्कि आपके निजी डेटा को भी खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अपने स्मार्टफोन में वायरस वाले ऐप्स को कैसे पहचानें और उनसे छुटकारा पाएं।

स्मार्टफोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बने चुका है। लेकिन जैसे-जैसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे ही वायरस और मालवेयर वाले ऐप्स का खतरा भी बढ़ा है। ये खतरनाक ऐप्स ने केवल आपके फोन की गति को धीमा कर सकते हैं, बल्कि आपके निजी डेटा को भी खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अपने स्मार्टफोन में वायरस वाले ऐप्स को कैसे पहचानें और उनसे छुटकारा पाएं।

वायरस की पहचान कैसे करें?

सबसे पहला तरीका है फोन की स्पीड धीमी हो जाना, अगर आपका फोन सामान्य से ज्यादा स्लो हो गया है, तो ये वायरस वाले ऐप्स का संकेत हो सकता है।

वहीं दूसरा तरीका है पॉप-अप विज्ञापन दिखना, इसमें अगर आपका फोन बार-बार अनचाहे विज्ञापन दिखा रहा है तो ये संकेत हो सकता है कि कोई ऐप आपके फोन को संक्रमित कर रहा है।

वहीं बैटरी तेजी से खत्म होना भी एक कारण हो सकता है आपके फोन में वायरस होने का। अगर आपका फोन भी बिना उपयोग के जल्दी बैटरी खत्म हो रही है तो किसी वायरस या मैलवेयर का शक हो सकता है।

अगर आपके फोन में ऐसे ऐप्स दिख रहे हैं जिन्हें आपने खुद इंस्टॉल नहीं किया, तो तुरंत अलर्ट हो जाएं।

इन तरीकों से वायरस से बचे

प्लेस्टोर से ऐप्स डाउनलोड करें

हमेशा भरोसेमंद सोर्स से ही ऐप्स डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर और ऐपल स्टोर सबसे सुरक्षित ऑप्शन है।

किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग और यूजर रिव्यू जरूर पढ़ें।

अपने फोन में अच्छे एंटीवायरस ऐप्स इंस्टॉल करें, जिसे आपके फोन को स्कैन करके वायरस वाले ऐप्स को हटा सकते हैं।

हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश एंबेसी के बाहर हिंदू संगठनों ने किया मार्च

संजय बाटला

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ दिल्ली में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश एंबेसी के बाहर विरोध मार्च निकाला। प्रधानमंत्री संग्रहालय तीन मूर्ति चौक से प्रारंभ हुआ मार्च चाणक्यपुरी थाने पर दाकर समाप्त हुआ। आरएसएस सिविल सोसाइटी ऑफ दिल्ली समेत कई संगठनों ने इस मार्च में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।

नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ चाणक्यपुरी में आरएसएस, सिविल सोसाइटी ऑफ दिल्ली समेत कई हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकाला। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत कर दिया था।

अधिकारियों ने कहा कि इस आंदोलन के कारण यातायात बाधित हुआ और यात्रियों को असुविधा हुई। चाणक्यपुरी में विरोध प्रधर्शन और मार्च में 200 से अधिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों ने हिस्सा लिया था।

प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से मांग करते हुए तख्तियां ले रखी थीं। उन्होंने बांग्लादेश से देश में कथित हिंदू नरसंहार को रोकने का भी आह्वान किया।

दिल्ली निवासी प्रदर्शनकारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, हम उसे देख रहे हैं। हम पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हैं। हम बांग्लादेश को देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन को तुरंत रोकने की चेतावनी देते हैं।

प्रधानमंत्री संग्रहालय, तीन मूर्ति चौक से प्रारंभ हुआ मार्च चाणक्यपुरी थाने पर दाकर समाप्त हुआ।

चाणक्यपुरी थाने के सामने बने मंच से साध्वी दीदी ऋतंभरा, इस्कॉन के केशव मुरारी, इंडिया सेंट्रल एशिया फाउंडेशन के निदेशक रमाकांत द्विवेदी, दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त एसएन श्रीवास्तव, बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीणा सिकरी, बौद्ध धर्मगुरु राहुल भंते, सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रियदर्शनी, लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता रूद्रनील घोष और कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं भाजपा सांसद अभिजीत गांगुली ने मार्च को संबोधित किया।

बांग्लादेश में आठ फीसदी हिंदुओं की आबादी

बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में हिंदुओं की संख्या करीब आठ फीसदी है। 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश के 50 से अधिक जिलों में हिंदुओं पर 200 से अधिक हमले होने के आरोप हैं।

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को AIMIM ने दिया टिकट, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2023 के लिए AIMIM ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। इसी क्रम में पार्टी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। ताहिर हुसैन पहले आम आदमी पार्टी में थे। अब ताहिर हुसैन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी खबर।

नई दिल्ली। दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। ताहिर हुसैन के परिवार ने मंगलवार को ओवैसी से मुलाकात भी की है। ताहिर हुसैन अभी तक आम आदमी पार्टी में थे।

2020 के दंगे में आया था नाम : ताहिर हुसैन के चुनावी मैदान में उतरने से मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रोचक हो गया है। ताहिर नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी से पार्षद रहे। वर्ष 2020 में दिल्ली दंगे में नाम सामने आने पर आप ने ताहिर को पार्टी से निकाल दिया था।

2020 से ही जेल में बंद है ताहिर हुसैन : बता दें कि ताहिर वर्ष 2020 से ही जेल में बंद है। उस पर यूएपीए, दंगे की साजिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। जेल में बंद रहने के दौरान भी ताहिर के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में हर त्योहार पर पोस्टर लगते हैं।

आम आदमी पार्टी की बढ़ गई चिंता : ताहिर के मैदान में उतरने के बाद आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। मुस्तफाबाद से मौजूदा विधायक हाजी यूनुस से ताहिर हुसैन की कभी बनी नहीं है।

क्या सियासी दलों पर भी लागू होगा पीओएसएच एक्ट ?

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह जवाब

राजनीतिक दलों में भी कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून लागू करने की मांग उठी है। सोमवार को याचिका पर देश की शीर्ष अदालत ने सुनवाई की। याचिका में मांग की गई कि अदालत सियासी दलों को अपने यहां आंतरिक शिकायत समितियां गठित करने का आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने याची को पहले चुनाव आयोग जाने को कहा है।

राजनीतिक दलों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोक कानून लागू करने और आंतरिक शिकायत समितियां गठित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पहले चुनाव आयोग के समक्ष मांग रखने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता तो वह फिर कोर्ट आ सकता है। ये आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने योगमाया एमजी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।

सोमवार को जब मामला सुनवाई पर आया तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि राजनैतिक दलों में भी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न कानून लागू होना चाहिए और कोर्ट राजनैतिक दलों में भी आंतरिक शिकायत समितियां गठित करने का आदेश दें, जहां यौन उत्पीड़न की शिकायत की जा सके।

तो क्या कानून लागू होना कठिन

पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि केरल हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि राजनैतिक दलों में नियोक्ता और कर्मचारी संबंध नहीं होता जिससे राजनैतिक दलों पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक कानून लागू होना कठिन हो जाता है। हालांकि यह कानून अन्य परिस्थितियों में भी लागू हो सकता है। वकील ने कहा कि कानून की धारा छह गठित स्थानीय समितियों में संविदा कर्मचारी या अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के लोगों के शिकायत करने की बात करती हैं।

छह सियासी दलों को बनाया प्रतिवादी

याचिका में मान्यता प्राप्त छह राजनैतिक दलों को प्रतिवादी बनाया गया था। वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ही राजनैतिक दलों का पंजीकरण करता है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि सक्षम अथॉरिटी यहां चुनाव आयोग है तो फिर याचिकाकर्ता को पहले चुनाव आयोग के समक्ष जाना चाहिए और अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता तो वह फिर से कोर्ट आ सकता है। वकील ने कोर्ट के सुझाव से सहमति जताई।

संसार और सन्यास को एक साथ साधने की शिक्षा देती है श्रीमद्भगवद्गीता

(डॉ. मुकेश "कबी"-विभूति फीचर्स)

गीता विश्व का सबसे अद्भुत ग्रंथ है, यह हर धर्म के लोगों को जिंदगी जीना सिखाता है, यही कारण है कि दुनिया के हर धर्म ग्रंथ पर गीता का प्रभाव देखा जा सकता है फिर चाहे बाइबिल हो या कुरान उनमें भी कहीं न कहीं गीता की बातें अवश्य मिल जाएंगी।असल में जिस वक्त गीता का जन्म हुआ तब दुनिया में सनातन के अलावा कोई और धर्म था ही नहीं इसलिए इसमें सिर्फ मानव जीवन के उपदेश ही मिलते हैं । इसमें सिर्फ धर्म और अधर्म दो पक्ष ही इसके दो केंद्र बिंदु दिखाई देते हैं । मानव जीवन भी सिर्फ धर्म और अधर्म दो बिंदुओं के बीच ही चलता है, गीता अधर्म के बजाए धर्म को बेहतर विकल्प मानती है इसीलिए मानव को धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करती है । सबसे खास बात तो यह है कि गीता के धर्म का वर्तमान के सम्प्रदायों से कोई संबंध नहीं है, सम्प्रदाय अलग बात है और धर्म बिल्कुल अलग । गीता में धर्म का संबंध हमारे स्वभाव से है न कि किसी संगठन, सम्प्रदाय या समूह से ।हमारा स्वभाव ही हमारा धर्म है इसीलिए हर सम्प्रदाय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों स्वभाव के लोग मिलते हैं । वर्तमान में संप्रदाय को ही धर्म मानकर धर्म को बहुत संकीर्ण कर दिया गया है इसीलिए दुनिया में अराजकता और अशांति है और इसकी जड़ है सभी सम्प्रदायों का अहंकार । आई एम द बेस्ट की भावना जबकि सच यह है कि कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है, सभी समान हैं क्योंकि धर्म नितांत व्यक्तिगत भाव है। वर्तमान परिवेश में इसको समझें तो हम कह सकते हैं कि हर सम्प्रदाय के धर्म गुरु ब्राह्मण है, हर सम्प्रदाय में जितने भी नेता और सैनिक हैं वो क्षत्रिय हैं, जितने भी व्यापारी हैं वो वैश्य हैं और जितने भी कर्मचारी हैं वो शूद्र हैं फिर इस से फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति या सम्प्रदाय के हैं लेकिन यह बात जरूर महत्वपूर्ण है वो अपने अपने काम स्वाभाविक रूप से करते हैं या पेट भरने के लिए करते हैं। यदि हम अपने जॉब से सेटिस्फाई हैं और उत्साह से करते हैं तो वो ही हमारा स्वभाव या धर्म है लेकिन मन मारकर काम करते हैं तो वो हमारा स्वाभाविक काम नहीं है सिर्फ जीवन यापन के लिए हम वो काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को ही गीता पापी मानती है । यदि हम सिर्फ अपने पेट और परिवार को पालने के लिए ही काम करते हैं तो गीता कहती है कि ऐसे लोग पाप करते हैं लेकिन वही काम हम खुश होकर करते हैं और जनकल्याण के लिए करते हैं तो वह धर्म बन जाता है, पुण्य हो जाता है, एक यज्ञ बन जाता है । आजकल यही देखने में ज्यादा आता है कि हमारा स्वभाव कुछ और है लेकिन हमें काम या जॉब कुछ और करना पड़ता है यही टेंशन क्रिएट करता है, इसी दुविधा से बचाने के लिए गीता कहती है कि स्वाभाविक कर्म ही करना चाहिए अर्थात जिसमें हमारा इंट्रेस्ट हो वही काम करना चाहिए जिससे शांति और संतुष्टि दोनों मिलती है ।आज समस्या यह है कि हमारे इंट्रेस वाले काम से हमें अनिंग होती है या नहीं ? तब गीता के अनुसार उसका एक ही समाधान है कि हम परिणाम या अनिंग की परवाह न करते हुए सिर्फ अपने काम के लिए ही काम करें बदले में जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहें या फिर जिस काम में हमें अनिंग होती है उसी में खुश रहने की कोशिश करें। खुशी ही सबसे बड़ी प्रेरणा है और टेंशन ही अवसाद और निष्क्रियता का जनक है। अर्जुन भी टेंशन में थे क्योंकि उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था और वे सब कुछ छोड़कर जान चाहते थे तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध ही तुम्हारा स्वभाव है युद्ध की छोड़कर कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, संन्यास अर्जुन का स्वभाव नहीं है, अर्जुन स्वभाव से क्षत्रिय है, योद्धा है, अर्जुन का स्वभाव ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है इसलिए संन्यास से अर्जुन को संतुष्टि नहीं मिल सकती ।व्यक्ति का स्वभाव बचपन से ही दिख जाता है, अर्जुन बचपन से ही तीरंदाजी में खुश रहते थे, वो तीरंदाजी में इतने डूबे हुए थे कि उनको अपने टारगेट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। श्रीकृष्ण भी अर्जुन को बचपन से ही जानते थे इसलिए उन्हें अर्जुन का स्वभाव पता था । वे जानते थे कि अर्जुन एक स्वाभाविक योद्धा हैं इसलिए उनको युद्ध ही करना चाहिए और इसके परिणाम के विषय में नहीं सोचना चाहिए। परिणाम के विषय में सोचने से ही सारा दुख और टेंशन क्रिएट होता है इसलिए गीता परिणाम के बजाय प्रैक्टिस पर जोर देती है । हम भी आम जीवन में यही महसूस करते हैं कि सारा टेंशन परिणाम पर विचार करने से ही होता है फिर चाहे एग्जाम की तैयारी हो या जॉब में प्रमोशन की या फिर सैलरी की चिंता हो, उसके बजाए हम सिर्फ काम को एंजॉय करें फिर सैलरी या प्रमोशन मनमाफिक मिले या न मिले । गीता के अनुसार डूबकर काम करना ही योग है और यही संन्यास है और यही धर्म भी है इसीलिए गीता में किसी तरह की यौगिक क्रियाओं का वर्णन नहीं मिलता। वास्तव में योगासनों का अर्थ योग नहीं है बल्कि एकाग्रता से काम करना ही योग है इसीलिए श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन योगी हो जाएं और अपना धनुष बाण चलाने में ही इतने डूब जाएं कि उन्हें परिमाणों की सुध ही न रहे इसी से अर्जुन को शांति प्राप्त होगी और तनाव समाप्त होगा। लेकिन जब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है श्रीकृष्ण के कारण ही युद्ध हुआ वरना युद्ध नहीं होता पर यह सच नहीं है क्योंकि अर्जुन यदि युद्ध से हट जाते तो भी युद्ध तो होना ही था ।उस समय शेष सभी योद्धा तो लड़ने को उतावले थे ही, वे अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच रहे थे, उनके मन में तो सिर्फ अपने शत्रु का विनाश ही था, वो लोग दृढ़ निश्चयी थे कि युद्ध करना ही है सिर्फ अर्जुन ही कन्फ्यूज्ड थे और कन्फ्यूज्ड लोगों के लिए गीता अमृत ही है । सही समाधान है शुद्ध औषधि है। श्रीकृष्ण जानते थे कि अन्य योद्धाओं के कारण युद्ध तो टल नहीं सकता फिर अर्जुन क्यों पलायन करे इसलिए अर्जुन की पलायनवादी सोच को दूर करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। इसमें अर्जुन सिर्फ एक माध्यम हैं । उनके माध्यम से हर मानव को श्रीकृष्ण का उपदेश है गीता क्योंकि मानव जीवन में इस तरह की स्थितियां सबके साथ निर्मित होती है, कई बार हम भी सब कुछ छोड़कर दूर जाना चाहते हैं, काम धंधा छोड़कर भागते हैं यहां तक कि घर परिवार को भी छोड़कर कहीं एकांत में चले जाना चाहते हैं लेकिन हम छोड़कर जा नहीं पाते क्योंकि जाएंगे कहां ? कहीं भी जाएं तो पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा । यही गीता कहती है कि बिना काम किए शरीर का पोषण संभव नहीं है इसलिए जब काम करना ही है तो वर्तमान काम को छोड़कर क्यों जाना ? वर्तमान काम ही हमारी नियति है इसलिए इसको पूरे मन से करें और मन को भी वर्तमान में रखे क्योंकि भूत और भविष्य का विचार ही दुख का कारण है । भविष्य की चिंता में हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होने का ही गीता विरोध करती है क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड होने से निगेटिविटी और डिप्रेशन आने लगते हैं फिर सारे काम रुक जाते हैं । कई बार परिणाम पर ज्यादा विचार करने से बीमारी भी होने लगती हैं। आजकल बीपी और डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम परिणाम की चिंता से घिरे रहते हैं जबकि परिणाम को छोड़कर काम करें तो शांति और खुशी मिलने लगती है। काम क्या करें और काम का चयन कैसे करें इस तरह की दुविधाओं से बचने के लिए हमें गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। दुनिया में गीता से बड़ी कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि सारी मोटिवेशन बुक्स की जननी भगवद्गीता ही है। गीता ही एकमात्र ग्रंथ है जो हमें संसार और संन्यास एक साथ साधने की शिक्षा देती है । धर्म और अधर्म में संतुलन बनाने की दिशा देती है और हमारा धर्म क्या है और हमें करना क्या चाहिए इसकी शिक्षा भी गीता में बहुत सरल तरीके से मिल जाती है। गीता इतनी सरल और सरस क्यों है क्योंकि यह स्वयं भगवान के ही उद्गार से जन्मी है। भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है पूर्ण पुरूषोतम हैं। वे इस जगत की और परा जगत की हर बात जानते हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई या सुनाई देता है श्रीकृष्ण वह सब जानते हैं। उनकी बाधाओं को भी जानते हैं और उन बाधाओं को पार कैसे करना है यह भी जानते हैं इसलिए वह स्वयं का अनुभव ही अर्जुन को बताते हैं और अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति को बताते हैं। इसीलिए मानव कल्याण का ग्रंथ है भगवद्गीता। गीता को अवश्य पढ़ें, और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें गीता को पढ़ना ज्ञान यज्ञ है और गीता का प्रचार करना ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा।इसका वर्णन स्वयं भगवान ने अठारहवें अध्याय में किया है इसलिए नियमित रूप से गीता पढ़े और पढ़ाएं तभी गीता की सार्थकता होगी और गीता जयंती भी सार्थक होगी। सभी को गीता जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

*

*(विभूति फीचर्स) * (लेखक*

कब तक दी जाएंगी मुफ्त चीजें', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल

परिवहन विशेष न्यूज

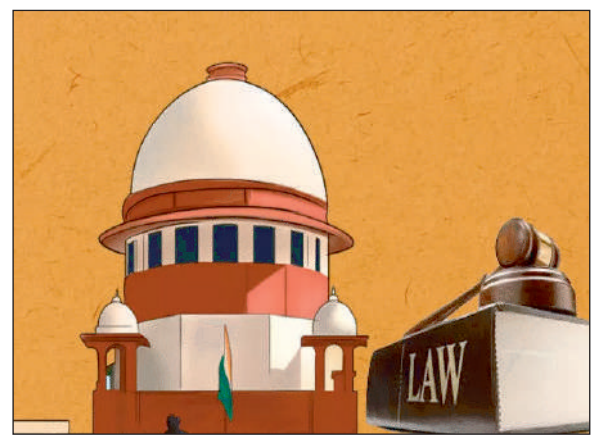

नई दिल्ली। 81 करोड़ लोगों को दिए जा रहे मुफ्त या रियायती राशन पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है और केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर कब तक मुफ्त में चीजें दी जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि हम इन प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर और क्षमता निर्माण पर क्यों नहीं काम करते। कोर्ट ने मामले पर और भी अहम टिप्पणियां कीं।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर देते हुए पूछा है कि लोगों को कब तक मुफ्त चीजें दी जा सकती हैं? जस्टिस सूर्यकांत और मनमोहन की पीठ उस समय हैरान रह गई, जब केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है।

इस पर पीठ ने कहा- इसका मतलब है कि केवल करदाता ही इससे वंचित हैं। शीर्ष अदालत कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रही है। एक एनजीओ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने पूछे सवाल

इस पर पीठ ने कहा, कब तक मुफ्त चीजें दी जा सकती हैं? हम इन प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर और क्षमता निर्माण पर क्यों नहीं काम करते? प्रशांत भूषण ने कहा कि इस अदालत द्वारा समय-समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वे केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठा सकें। नवीनतम आदेश में कहा गया है कि यदि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है और अगर वह ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो उसे भी केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन दिया जाएगा।

खुश करने के लिए जारी करते हैं राशन कार्ड: कोर्ट

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यही समस्या है। जिस क्षण हम राज्यों को सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का निर्देश देंगे, एक भी प्रवासी श्रमिक यहां नहीं दिखेगा। वे भाग जाएंगे। लोगों को खुश करने के लिए राज्य राशन कार्ड जारी कर सकते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि यदि जनगणना 2021 में की गई होती, तो प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती, क्योंकि केंद्र वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है।

बचपन का गाँव

ठण्डी-ठण्डी छांव में
उस बचपन के गाँव में
मैं-जाना चाहती हूँ।
तोडना चाहती हूँ
बंदिश चारों पहर की।
नफरत भरी ये
जिन्दगी शहर की॥
अपनेपन की छाया
मैं पाना चाहती हूँ।
उस बचपन के गाँव में
मैं-जाना चाहती हूँ॥
घुट-सी गयी हूँ
इस अकेलेपन में
खुशियों के पल ढूँढ रही
निर्दयी से सूनेपन में
इस उजड़े गुलशन को
मैं महकाना चाहती हूँ।
उस बचपन के गाँव में
मैं-जाना चाहती हूँ।
प्रेम और भाईचारे का
जहाँ न संगम हो।
भागे एक-दूजे से दूर
न मिलन की सरगम हो॥
उस संसार से अब
मैं छुटकारा चाहती हूँ।
उस बचपन के गाँव में
मैं-जाना चाहती हूँ।

—प्रियंका 'सौरभ'

अजनबी हो तुम, मौन हो तुम।

मेरे लिए तो बस अजनबी हो तुम,
मैंने जबसे तुम्हें देखा मौन हो तुम।
क्यों? मुझे देखते हो चुपके-चुपके,
अपने दोस्त के साथ रुकते-रुकते।
जब भी देखती आपका वह लुक,
बस वहाँ नजरे मेरी जाती है झुक।

मेरे लिए तो बस अजनबी हो तुम,
मैंने जबसे तुम्हें देखा मौन हो तुम।
क्यों? आने लगे हो मेरे ख्वाबों में,
बस जाने लगे हो मेरी ही यादों में।
तक रही राह आपके इजहार की,
कब खत्म होगी घड़ी इंतजार की।

मेरे लिए तो बस अजनबी हो तुम,
मैंने जबसे तुम्हें देखा मौन हो तुम।
सनम एक झलक दिखला जाओ,
ख्वाबों में नहीं हकीकत में आओ!
पलके बिछाए खड़ी हूँ, हो सके तो,
अपनी दुल्हनिया बनाकर ले जाओ।

संजय एम तराणेकर

न्यूरॉन्स की गतिविधि से पकड़ में आएगी दिमाग की बीमारी, AI से होगी ब्रेन की स्टडी

परिवहन विशेष न्यूज

एनबीआरसी के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और एल्गोरिथ्म डेवलपमेंट का उपयोग करके ब्रेन स्कैन की स्टडी की और पाया कि हर मानसिक बीमारी का अपना एक विशेष पैटर्न होता है। इस शोध से मानसिक बीमारियों के इलाज में क्रांति आने की उम्मीद है। इसके अलावा कई बीमारियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसका इलाज भी आसान होगा।

विज्ञानी अर्पण बनर्जी

डा. प्रवीण गुप्ता, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ न्यूरोलॉजी, फोर्टिस अस्पताल

विज्ञानी अर्पण बनर्जी, अपनी टीम के साथ चर्चा करते हुए।

ग्रेटर नोएडा। गुरुग्राम। मस्तिष्क की जटिलता को समझना जितना कठिन है, उसी अनुपात में इससे जुड़ी बीमारियों का इलाज भी, लेकिन नए शोध दिमाग के रहस्य की परतों को खोल रहे हैं। मस्तिष्क पर शोध करने वाले संस्थान राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी) ने सिजोफ्रेनिया जैसी ही घातक कई अन्य मानसिक बीमारियों के इलाज को लेकर नई उम्मीद जगाई है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और अल्बोरिज्म डेवलप का प्रयोग कर ब्रेन स्कैन की स्टडी की गई तो पता चला कि हर मानसिक बीमारी का अपना एक विशेष पैटर्न होता है। चार साल तक अलग-अलग मानसिक बीमारियों से ग्रसित 400 मरीजों पर गहराई से शोध कर यह निष्कर्ष निकाला गया।

यह शोध प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल नेचर पब्लिशिंग ग्रुप में भी प्रकाशित हुआ है। शोध में डॉक्टरों ने पाया कि न्यूरांस की सक्रियता के कारण हर बीमारी का अपना पैटर्न बनता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि बीमारियों के अलग पैटर्न को समझने से जहां बीमारियों की जटिलता को समझने में मदद मिलेगी, वहीं इनके इलाज में प्रयोग होने वाली दवाओं के अनुसंधान में भी क्रांति आएगी।

भारतीय जनसंख्या का पांच प्रतिशत प्रभावित

विज्ञानियों के अनुसार भारत में मानसिक रोगियों की संख्या का सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन सिजोफ्रेनिया, पोस्ट-ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या भारत की कुल आबादी में पांच प्रतिशत तक हो सकती है।

मानसिक बीमारियों के प्रति आज भी लोगों में काफी भ्रांतियां हैं। ऐसे में सभी मरीज चिकित्सकों तक पहुंच भी नहीं पाते या फिर वह किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, इसे ही नहीं समझ पाते।

एमआरआई रिपोर्ट को एआई की मदद से किया एनालाइज

वैज्ञानिक अर्पण के अनुसार एमआरआई रिपोर्ट को एनालाइज करते एआई के माध्यम से मानसिक डिसऑर्डर के बारे में बताया जा सकता है। अभी तक विभिन्न प्रकार के मानसिक डिसआर्डर के बीच अंतर करने के लिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन और मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) का ही प्रयोग होता है।

टीम ने शोध में इसी पर काम किया है कि कैसे सिर की एमआरआई रिपोर्ट से हासिल जानकारी से बीमारी की पहचान की जा सके। रिसर्च पेपर में भी यही बताया कि कुछ डिसऑर्डर एमआरआई से बताए जा सकते हैं लेकिन बायपोलर, सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी के संबंध नहीं बताया जा सकता है। ब्रेन इमेजिंग के डेटा को एआई अल्वोरिज्म के माध्यम एनालाइज कर डिसऑर्डर की पहचान की जाती है।

इन बीमारियों की पहचान में मिलेगी मदद

एनबीआरसी के विज्ञानी अर्पण बनर्जी के अनुसार एआई का प्रयोग करके एमआरआई डेटा से बता सकते हैं कि किसी मरीज में कौन-सा न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं। जैसे एंग्जायटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, विभिन्न प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, पोस्ट-ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया।

इलाज में होगी आसानी

फोर्टिस अस्पताल के प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ न्यूरोलॉजी डॉ. प्रवीण गुप्ता इस शोध में मिली सफलता पर कहते हैं कि किसी मानसिक डिसऑर्डर की पहचान करना काफी जटिल काम है। अधिकतर बीमारियां बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया या मष्तिस्क में असंतुलन के कारण होती हैं। चूंकि, सीटी और एमआरआई में दिमाग के ढांचे की जांच होती है ब्रेन के ट्रांसमीटर और फंक्शन की नहीं।

इस कारण डॉक्टर इन बीमारियों के डायग्नोसिस नहीं बना पाते हैं। जिस कारण इन बीमारियों की पहचान करना मुश्किल है। यह शोध काफी कारगर है, क्योंकि कई मामलों में बीमारी का पता नहीं चलने से मरीज इलाज के लिए सहमत नहीं होता है। यदि हम इमेजिंग या टेस्ट से बीमारी की पहचान कर पाएंगे तो मरीजों का विश्वास भी बढ़ेगा और सही इलाज भी हो सकेगा।

मस्तिष्क की जटिलताओं के शोध के लिए मैपिंग करते हुए विज्ञानी अर्पण बनर्जी की टीम के सदस्य।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, 10 से 14 दिसंबर तक इन मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया के मद्देनजर 10 से 14 दिसंबर तक ट्रैफिक बदला रहेगा। चिल्ला रेड लाइट से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात को सेक्टर-14ए फ्लाईओवर से गोलचक्कर चौक सेक्टर 15 की ओर डायवर्ट किया जाएगा। डीएनडी से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात को रजनीगंधा चौक सैक्टर 16 की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अगले कुछ ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया 2024 कार्यक्रम के मद्देनजर 10 से 14 दिसंबर तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किए हैं।

विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए 14 मार्गों पर डायवर्जन लागू किया है। आइए जानते हैं किन रास्तों पर आवाजाही में बदलाव किया गया है...

इन रास्तों पर आवाजाही में किया गया है बदलाव

- चिल्ला रेड लाइट से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात को सेक्टर-14ए फ्लाईओवर से गोलचक्कर चौक सेक्टर 15 की ओर डायवर्ट किया जाएगा। इस रूट के वाहन डीएससी मार्ग होकर गंतव्य की ओर जा सकेंगे।
- डीएनडी से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात को रजनीगंधा चौक सैक्टर 16 की ओर डायवर्ट किया जाएगा। इस रूट के वाहन एमपी-1 मार्ग व डीएससी मार्ग होकर गंतव्य की ओर जा सकेगा।
- कालिंदी कुंज बॉर्डर से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात को महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37 की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात एमपी-03 मार्ग व डीएससी मार्ग होकर गंतव्य की ओर जा सकेगा।
- सेक्टर 37 से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात को सेक्टर 44 गोल चक्कर से डबल सर्विस रोड पर डायवर्ट किया जायेगा। यह यातायात डबल सर्विस रोड से होकर डीएससी मार्ग से अपने गंतव्य को जा सकेगा।
- आगरा से नोएडा की ओर से आने वाला यातायात जेवर टोल से आगे कस्बा जेवर की ओर उतरकर साबौता अंडरपास से खुर्जा बाईपास से जहांगीरपुर होकर गंतव्य की ओर जा सकेगा।
- परीचौक से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात को परी चौक से सूरजपुर की ओर डायवर्ट किया जायेगा। यह यातायात सूरजपुर से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होकर गन्तव्य को जा सकेगा।
- सूरजपुर से परी चौक की ओर जाने वाले यातायात को एलजी गोल चक्कर से 130 मीटर रोड की ओर डायवर्ट किया जायेगा। यह यातायात 130 मीटर रोड से होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा।
- एलजी गोलचक्कर से एक्सपो मार्ट गोलचक्कर होकर नोएडा की ओर जाने वाला यातायात एलजी गोलचक्कर से यू-टर्न लेकर सूरजपुर, कुलेसरा, फेज-2, एनएसईजेड होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा।
- पी-3 गोलचक्कर से परी चौक होकर सूरजपुर/ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ओर जाने वाले यातायात को पी-3 गोलचक्कर से स्वर्ण नगरी गोलचक्कर की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात 130 मीटर रोड से होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा।
- आगरा से नोएडा की ओर से आने वाला यातायात हिन्डन कट से सेक्टर 151 की ओर डबल सर्विस रोड होकर गंतव्य की ओर जा सकेगा।
- ग्रेटर नोएडा से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होकर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात को चरखा गोल चक्कर से सेक्टर-94 की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37 होकर गन्तव्य को जा सकेगा।
- जीआईपी की ओर से फिल्म सिटी फ्लाईओवर होकर डीएनडी की ओर जाने वाला यातायात फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न से डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात डीएससी मार्ग व एलिवेटेड मार्ग से गंतव्य की ओर जा सकेगा।
- रजनीगंधा की ओर से डीएनडी फ्लाईओवर होकर दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात रजनीगंधा चौक से डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात डीएनडी मार्ग होकर न्यू अशोक नगर बॉर्डर से गन्तव्य की ओर जा सकेगा।
- गोलचक्कर चौक सेक्टर-15 की ओर से सेक्टर 14ए फ्लाईओवर होकर दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात गोलचक्कर चौक से डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात न्यू अशोक नगर बॉर्डर से गंतव्य की ओर जा सकेगा।

आपातकालीन वाहनों की कराई जाएगी आवाजाही

यातायात पुलिस ने बताया कि आपातकालीन वाहनों की आवश्यकता अनुसार आवाजाही कराई जायेगी।

यमुना एक्सप्रेस पर तय हुई स्पीड लिमिट, इस तारीख से आदेश का करना होगा पालन

यमुना एक्सप्रेस-वे पर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक अधिकतम गति सीमा 75 किमी प्रति घंटा होगी। कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। प्रवेश व निकासी द्वार पर फॉग लाइट लगाने के भी कंपनी को निर्देश दिए गए हैं।

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे पर 15 दिसंबर से वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 75 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। यह गति सीमा 15 फरवरी तक लागू रहेगी।

सर्दियों में कोहरे के कारण होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए गति सीमा कम करने का फैसला लिया है। एक्सप्रेस-वे की संचालक कंपनी को यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) ने पत्र भेजकर इसकी जानकारी दे दी है।

तेज रफ्तार वाहनों के साथ हादसों की आशंका

प्रवेश व निकासी द्वार पर फॉग लाइट लगाने के भी कंपनी को निर्देश दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से आगरा (Greater Noida to Agra) तक 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा सौ किमी प्रति घंटा निर्धारित है, लेकिन सर्दियों में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है। इस कारण एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार वाहनों के लिए दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

हर साल दो माह तक कम होती है स्पीड लिमिट

इसलिए प्राधिकरण हर वर्ष दो माह के लिए एक्सप्रेस-वे पर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा (Speed Limit) कम कर देता है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि एक्सप्रेस-वे का संचालन कर रही जेपी इंफ्राटेक (Jaypee Infratech) को गति सीमा कम करने के संबंध में पत्र भेज दिया गया है।

वाहन चालकों को किया जाएगा जागरूक

इससे पहले वाहन चालकों की जागरूकता के लिए बोर्ड लगाने, प्रवेश व निकासी द्वार पर फाग लाइट लगाने, वाहन चालकों के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम व रेडियो से सूचना प्रसारित कराने के अलावा रिफ्लेक्टिव टेप लगाने और पैफ्लेट वितरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार व रविवार को वाहनों के अधिक दबाव को देखते हुए प्रभावी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

भारतीय संसदीय शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024-संसद की लड़ाई अदानी से होकर सोरोस पर आई-दुनियाँ की जनता देखती रही

शीतकालीन सत्र में दिल्ली का पारा गिरता जा रहा है परंतु संसद में सियासी तापमान प्रचंड है. डिजिटल मीडिया युग में सम्माननीय संसद सदस्यों को करोड़ों आंखें लाइव देख रही है जिसे हर सदस्य ने स्वत: संज्ञान लेना जरूरी है- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर दुनिययाँ के अनेकों लोकतांत्रिक देश में वहां के निचले व उच्च सदन के लिए निर्वाचित सदस्यों के बीच सदन जूते चप्पलों का चलना कुर्सियां फेंकना व आपसी मारपीट के अनेक मामले हम टीवी चैनलों के माध्यम से देख चुके हैं जो एक लोकतंत्र के मंदिर में किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जहां सकता यह उस जनता का अपमान है जिन्होंने उन्हें का समाधान करने वह उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए उन्हें चुना है। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक चलने वाले भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र में हम पहले दिन से ही देख रहे हैं कि काफी हंगामा मचा हुआ है,सदन नहीं चल रहा है व लगातार स्थगित हो रहे हैं। मंगलवार 10 दिसंबर 2024 को को 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। हंगामे के चलते पहले 12 बजे तक सदन स्थगित कर किया गया।12 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद भी अडाणी-जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर हंगामा जारी रहा, स्पीकर ने बुधवार तक के लिए सदन स्थगित कर दिया।विपक्ष लगातार उद्योगपति मामले पर जेपीसी की मांग कर रहा है जिसपर सदन में चर्चा हो परंतु अब सत्ता पक्ष मैं भी जार सोरोन का मुद्दा उठाकर बड़ी पार्टी को भी घेरा है जिससे अब और भी स्थिति गंभीर होती जा रही है जनता देख रही है पिछले, कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं कि लोकसभा सत्र के दौरान ही कोई गंभीर मुद्दा उठता है और उसपर हंगामा शुरू हो जाता है और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा यूं ही अपव्यय हो जाता है।चूँकि भारतीय संसदीय शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक चल रहा है, संसद की लड़ाई अदानी से होकर सोरोस पर आई-दुनियाँ की जनता देखती रही।

साथियों बात अगर हम हंगामेंदार शीतकालीन सत्र की करें तो शीतकाल में दिल्ली का पारा गिरता जा रहा है लेकिन संसद में सियासी तापमान प्रचंड है।शुरुआती छह में से पांच दिनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद कामकाज पटरी पर लौटा ही था कि दोनों ही सदन फिर से बेपटरी हो गए हैं। लोकसभा से राज्यसभा तक अडानी मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है तो वहीं अब दोनों सदनों में ट्रेजरी बेंच भी फ्रंटफुट पर आ गया है।संसद में अडानी मुद्दे से शुरू हुआ संग्राम अब जॉर्ज सोरोस पर आ गया है संसद के शुरुआती हफ्ते में जहां विपक्ष का अडानी पर आक्रामक रवैया सदन की कार्यवाही में बाधा बना तो वहीं अब विपक्ष के इस मुद्दे का जवाब सत्ता पक्ष के सदस्य संसद में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से दे रहे हैं।सत्ता पक्ष ने सोमवार को सोरोस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।विपक्ष के नेता ने कहा है कि अगर ये तय करके आए हैं कि सदन नहीं चलने देंगे तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।केरल के सांसद ने कहा कि सोरोस के मुद्दे पर चर्चा हो लेकिन उसके साथ ही अडानी मुद्दे पर भी चर्चा हो।कांग्रेस के सांसदों ने सत्ता पक्ष के रवैये को अडानी को बचाने की कोशिश बताया।विपक्ष के सदस्यों के विरोध के बाद संसद के दोनों

सदनों की कार्यवाही सोमवार को दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों का दावा है कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के उनके अनुरोध को सत्ता पक्ष द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इनमें दिल्ली में किसानों का विरोध प्रदर्शन और मणिपुर में चल रहा संघर्ष शामिल है। वहीं, दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक (एफडीएल-एपी) फाउंडेशन के जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ कथित संबंध के बारे में दावा किया है।

साथियों बात अगर हम अडानी बानाम सोरोस की करें तो संसद में सोरोस का मुद्दा आज गतिरोध बनकर सामने आया है लेकिन यह चैप्टर आज ही शुरू नहीं हुआ है, इसकी झलक 6 दिसंबर, शुक्रवार को ही देखने को मिल गई थी, तब अडानी मुद्दे पर हमलावर विपक्ष और कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया था, झारखंड के सांसद ने सोरोस का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी कांग्रेस से 10 सवाल पूछे थे। उन्होंने विपक्ष के नेता की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोरोस के किसी करीबी शेट्टी के नाम का जिक्र करते हुए भी सवाल पूछा था, इसी दौरान हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई थी।केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कार्यवाही शुरू होने से पहले कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम इसे विपक्षी पार्टी या विपक्षी नेता से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते, हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, यह भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है, हमने कांग्रेस और अन्य दलों से कहा है कि हम 13-14 दिसंबर (लोकसभा में) और 16-17 दिसंबर (राज्यसभा में) को संविधान पर चर्चा करेंगे।कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उसके कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर उनके नेताओं के भी भारत विरोधी ताकतों से संबंध पाए जाते हैं तो उन्हें भी अपनी आवाज उठानी जरूर चाहिए।

साथियों बात अगर हम जॉर्ज सोरोस को जानने की करें तोभारत की राजनीति में अमेरिका के अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस का नाम इन दिनों चर्चाओं में चल रहा है। बीजेपी ने विपक्षी बढ़ी पार्टी और विपक्ष के नेता समेत उनके परिवार की आलोचना करने के लिए सोरोस के नाम का सहारा लिया है। इतना ही नहीं बीजेपी ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता पर भारत को कथित तौर पर अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। सत्ताधारी पार्टी लगातार सोरोस का नाम लेकर विपक्ष के नेता को घेर रही है। सत्ताधारी पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की जिसको लेकर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सत्ताधारी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस नेता उस संगठन से जुड़ी हैं जो सोरोस से फंड लेती हैं।जॉर्ज सोरोस का नाम भारत में पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी सोरोस का नाम आ चुका है। इससे पहले अडाणी मुद्दे, मोदी सरकार पर टिप्पणी करके वह विवादों में आए थे। हंगरी के बुडापेस्ट में 1930 में सोरोस का जन्म हुआ था। सोरोस का नाता विवादों से रहा है। सोरोस का सबसे विवादित फाइनेंशियल मूव 1992 में आया था, उस समय उन्होंने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ दांव लगाया और एक ही दिन में 1 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की। इसके बाद उन्हें द मैन हू ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड का उपनाम भी दिया गया, जिसका अर्थ होता है-बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वाला व्यक्ति। पीएम मोदी के है धुर आलोचक है,जॉर्ज सोरोस की पहचान एक ऐसे व्यक्ति की रही है जो विश्व के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने के लिए अपना एजेंडा चलाता है। सोरोस को भारतीय पीएम की नीतियों का भी धुर आलोचक माना जाता है। 2020 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर एक भाषण के दौरान सोरोस ने पीएम और उनकी सरकार की खूब आलोचना की थी। उन्होंने सरकार परअधिनायकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया था। इसके अलावा सरकार पर विभाजनकारी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया। पीएम को सोरोस ने विश्व स्तरपर लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाले राष्ट्रवादी नेताओं में से एक बताया था। सोरोस के इस बयान की भारतीय नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी।

क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारतीय संसदीय शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024-संसद की लड़ाई अदानी से होकर सोरोस पर आई-दुनियाँ की जनता देखती रही शीत कालीन सत्र में दिल्ली का पारा गिरता जा रहा है परंतु संसद में सियासी तापमान प्रचंड है।डिजिटल मीडिया युग में सम्माननीय संसद सदस्यों को करोड़ों आंखें लाइव देख रही है जिसे हर सदस्य ने स्वतः संज्ञान लेना जरूरी है।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

EV Drive the Future

हिमाचल प्रदेश सरकार 41 स्थानों पर करेगी ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित

परिवहन विशेष न्यूज

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में परिवहन विभाग और दो कंपनियों के बीच राज्य सरकार द्वारा चिन्हित चार ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके तहत जियो-बीपी कंपनी मंडी-जोगिंदरनगर पठानकोट के साथ-साथ कीरतपुर-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी, जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी कंपनी एक साल के भीतर परवाणू-ऊना-संसारपुर टैरेस-नूरपुर और परवाणू, शिमला-रिकांगपिओ-लोसर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी। इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी। इन पांच ग्रीन कॉरिडोर पर कंपनियां एक साल के भीतर 41 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं और सुपरमार्केट स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 41 स्थानों पर ई-बस, ई-ट्रक और अन्य ई-वाहनों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही इन स्थानों पर शौचालय और रेस्तरां जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि कंपनियां राज्य सरकार को प्रति वर्ष लगभग 75 लाख रुपये लीज मनी के रूप में प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश को ई-वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम करके राज्य के पर्यावरण को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित किया जाएगा।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार 350 ई-बसें भी खरीदने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य का परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग है, जहां सभी वाहन इलेक्ट्रिक हैं। राज्य में ग्रीन कॉरिडोर स्थापित होने से निजी वाहन मालिकों को भी ई-वाहनों के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी की ओर से राहुल सोनी और जियो बीपी कंपनी की ओर से अविनाश शर्मा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आरडी नाजिम और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

ईका मोबिलिटी को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से 150 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रिक बस का मिला ऑर्डर

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और तकनीक में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी ईका मोबिलिटी ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से लगभग 150 करोड़ रुपये के दो ऑर्डर मिलने की घोषणा की है।

इस ऑर्डर में 40 ईका 12, 12-मीटर एसी इलेक्ट्रिक बसों और 30 ईका 9, 9-मीटर एसी इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति और रखरखाव शामिल है। इन वाहनों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े को पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के साथ बढ़ाना है, जो सुरक्षा, यात्री आराम और परिचालन दक्षता को प्राथमिकता देते हैं। कंपनी सुचारू संचालन का समर्थन करने के लिए चार्जर भी प्रदान करेगी। दोनों परियोजनाओं में अगले 10 वर्षों के लिए लगातार प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एक दीर्घकालिक वार्षिक रखरखाव अनुबंध शामिल है।

ईका मोबिलिटी के मुख्य विकास अधिकारी रोहित श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ मिलकर काम करने की कंपनी की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर भारत में टिकाऊ और कुशल गतिशीलता समाधान प्रदान करने पर ईका मोबिलिटी के फोकस को दर्शाते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किए गए इन नए वाहनों से राज्य के स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर बढ़ने में योगदान मिलने की उम्मीद है।

पिनेकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी ईका मोबिलिटी भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एक उभरती हुई कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक बसों और वाणिज्यिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करती है। पुणे में मुख्यालय वाली यह कंपनी भारत के स्वच्छ परिवहन प्रणाली में परिवर्तन का समर्थन करते हुए टिकाऊ गतिशीलता समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करना चाहती है।

ईका मोबिलिटी शहरी और अंतर-शहरी परिवहन दोनों के लिए डिज़ाइन किए गए 9-मीटर और 12-मीटर वेरिएंट सहित इलेक्ट्रिक बसों की एक श्रृंखला प्रदान करती है। इन वाहनों में उन्नत इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन, ऊर्जा-कुशल डिज़ाइन और सुरक्षा प्रणालियाँ हैं जो इष्टतम प्रदर्शन और यात्री आराम सुनिश्चित करती हैं। विनिर्माण के अलावा, कंपनी अपने ग्राहकों के लिए निर्बाध संचालन की सुविधा के लिए चार्जिंग समाधान और दीर्घकालिक रखरखाव अनुबंध प्रदान करती है।

कंपनी ने सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए राज्य परिवहन निगमों और निजी ऑपरेटरों के साथ सहयोग किया है। इसकी परियोजनाओं में अक्सर व्यापक समर्थन शामिल होता है, जैसे चार्जर इंस्टॉलेशन और फ्लीट प्रबंधन सेवाएँ, जो कुशल तैनाती और संचालन सुनिश्चित करती हैं।

ईका मोबिलिटी वाहन दक्षता, बैटरी प्रौद्योगिकी और स्मार्ट कनेक्टिविटी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास में भी शामिल है। टिकाऊ डिजाइन और परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करके, ईका मोबिलिटी का लक्ष्य वाहन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के भारत के लक्ष्यों में योगदान देना है। इसके प्रयास FAME योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकार की पहल के अनुरूप हैं।

स्टेटिक और वर्टेलो ने ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए मिलाया हाथ

परिवहन विशेष न्यूज

स्टेटिक और वर्टेलो ने देश के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। स्टेटिक ईवी चार्जर के माध्यम से हार्डवेयर और चार्जिंग इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग सेवाओं के माध्यम से इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण के रूप में सॉफ्टवेयर दोनों प्रदान करेगा।

दोनों मिलकर भारत के ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए काम करेंगे। स्टेटिक के संस्थापक और सीईओ अक्षित बंसल ने यह भी कहा कि यह साझेदारी वर्टेलो के वित्त विकल्पों को कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के साथ सामंजस्य बिठाकर टिकाऊ भविष्य के लिए काम करने के लिए अनंत अवसर प्रस्तुत करती है।

स्टेटिक के पास अब 65 शहरों में 7,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट हैं, जिनमें बड़े महानगरीय क्षेत्र और मध्यम आकार के शहर भी शामिल हैं। कंपनी की सामान्य रणनीति 2025 से पहले 20,000 नए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना है, और इस लक्ष्य को आदर्श बनाने के लिए वर्टेलो के साथ सहयोग बहुत ज़रूरी है। वर्टेलो के सीईओ संदीप गंभीर ने इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव को आसान बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर ज़ोर दिया, और स्टेटिक के साथ मिलकर काम करने से बदलाव का समर्थन करने के लिए मज़बूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित होता है।

महिंद्रा की गाड़ियों पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट, एक्सयूवी 400 पर 3 लाख रुपये तक की छूट

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा एसयूवी पर छूट 2024 दिसंबर 2024 में महिंद्रा की गाड़ियों पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी दिसंबर 2024 में त्योहारी सीजन से ज्यादा डिस्काउंट दे रही है। साल के आखिरी महीने में महिंद्रा की XUV400 पर 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इसके साथ ही महिंद्रा स्कॉर्पियो और बोलेरो पर भी एक लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।

नई दिल्ली। दिसंबर 2024 में महिंद्रा की गाड़ियों पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। दरअसल कंपनी अपने पुराने स्टॉक को नए साल से पहले खाली करने का प्रयास कर रही है। वहीं, दिसंबर में मिल रहा डिस्काउंट ऑफर दिवाली के दौरान दिए गए ऑफर्स से ज्यादा हैं। आइए जानते हैं कि महिंद्रा की SUVs गाड़ियों पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है।

Mahindra XUV400

डिस्काउंट– 3.1 लाख रुपये तक

महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दिसंबर 2024 में 3.1 लाख रुपये तक छूट मिल रही है। इसके केवल XUV400 के टॉप-स्पेक EL Pro वेरिएंट पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें 39.4kWh और 34.5kWh का बैटरी पैक दिया गया है। Mahindra XUV400 की भारत में एक्स-शोरूम कीमत 16.74 लाख रुपये से 17.69 लाख रुपये तक है।

Mahindra XUV300

डिस्काउंट– 1.8 लाख रुपये तक

इसके टॉप-स्पेक W8 डीजल वेरिएंट्स पर 1.8 लाख रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, इसके टॉप-स्पेक W8 पेट्रोल वेरिएंट्स पर 1.5 लाख रुपये से 1.6 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। वहीं, इसके W4 और W6 वेरिएंट्स पर 95,000 रुपये लेकर से 1.34 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि W2 वेरिएंट्स पर 45,000 रुपये तक की छूट है।

Mahindra Bolero

डिस्काउंट– 1.5 लाख रुपये तक

महिंद्रा बोलोरो पर दिसंबर 2024 में 1.5 लाख रुपये तक तक का डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी टॉप-स्पेक B6 Opt वेरिएंट पर। इसके साथ ही मिड-स्पेक B6 और B4 ट्रिम्स पर 79,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। भारत में महिंद्रा बोलोरो 9.79 लाख रुपये से 10.91 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में आती है।

Mahindra Bolero Neo

डिस्काउंट– 1.5 लाख रुपये तक

बोलेरो नियो के टॉप-स्पेक N10 और N10 Opt वेरिएंट्स पर 1.5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही N8 पर 1.1 लाख रुपये तक और एंट्री-लेवल N4 पर 90,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। बोलेरो नियो की भारत में एक्स-शोरूम कीमत 9.95 लाख रुपये से लेकर 12.15 लाख रुपये तक है।

Mahindra Scorpio

डिस्काउंट– 1.45 लाख रुपये तक

महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक पर 1.45 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके टॉप-स्पेक S11 वेरिएंट्स पर 95,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसके साथ ही स्कॉर्पियो N के मिड-स्पेक Z4 और Z6 वेरिएंट्स पर 70,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके टॉप-स्पेक Z8 वेरिएंट्स पर 30,000 रुपये से लेकर 55,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।

Mahindra XUV700

डिस्काउंट– 80,000 रुपये तक

महिंद्रा XUV700 पर दिसंबर 2024 में 80,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यह डिस्काउंट एंट्री-लेवल MX और मिड-स्पेक AX3 और AX5 वेरिएंट्स पर दिया जा रहा है। XUV700 के टॉप-स्पेक AX7 और ZX7 L वेरिएंट्स पर 30,000 रुपये से लेकर 55,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

ईस्टमैन ऑटो एंड पावर ने 170 से अधिक एसकेयु के साथ इन्वर्टर बैटरी पोर्टफोलियो का किया विस्तार

परिवहन विशेष न्यूज

पावर सॉल्यूशन सेक्टर की प्रमुख कंपनी ईस्टमैन ऑटो एंड पावर ने अपने इन्वर्टर बैटरी पोर्टफोलियो का व्यापक विस्तार शुरू किया है। कंपनी ने ईस्टमैन ब्रांड के तहत 100 से अधिक नए मॉडल और अपने सहयोगी ब्रांड अड्डो के तहत 70 से अधिक मॉडल पेश किए, जिससे एसकेयु की कुल संख्या 170 से अधिक हो गई। विस्तारित रेंज में 100Ah से लेकर 400Ah तक की क्षमताएं शामिल हैं, जो भारत में उपलब्ध सबसे अधिक क्षमता है।

इस लॉन्च के हिस्से के रूप में, ईस्टमैन चुनिंदा मॉडलों पर विस्तारित वारंटी अवधि की पेशकश कर रहा है, जिसमें कुछ बैटरियां 20 साल तक के लिए कवर की गई हैं। नई रेंज को आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों सहित विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

लॉन्च के बारे में बात करते हुए ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शेखर सिंघल ने कहा, ₹यह विस्तार पूरे भारत में विश्वसनीय ऊर्जा समाधान प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों की एक श्रृंखला के साथ, हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों की विविध बिजली आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला प्रदर्शन और दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।₹

कंपनी के नए पोर्टफोलियो को तीन सीरीज में बांटा गया है: बजट के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट सीरीज, मूल्य-उन्मुख खरीदारों के लिए रेगुलर सीरीज और प्रीमियम सीरीज, जिसमें उच्च-मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई 400Ah बैटरी जैसे उच्च-क्षमता वाले विकल्प शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ईस्टमैन विभिन्न इंस्टॉलेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंबो शॉर्ट ट्यूबलर, शॉर्ट टॉल ट्यूबलर और टॉल ट्यूबलर सहित विभिन्न प्रकार के बैटरी कंटेनर प्रदान करता है।

ईस्टमैन का विस्तार भारतीय इन्वर्टर बैटरी बाजार में इसकी स्थिति को मजबूत करता है, जिसका लक्ष्य व्यापक ग्राहक आधार की जरूरतों को पूरा करने वाले समाधानों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराना है।

मिर्जापुर में ऑटो और ई-रिक्शा के लिए लागू होगा कलर कोड

परिवहन विशेष न्यूज

मिर्जापुर शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात और परिवहन विभाग ऑटो और ई-रिक्शा के लिए कलर कोड और रूट निर्धारित करने की तैयारी कर रहा है। रूट निर्धारित होने के बाद नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

शहर के रमईपट्टी, तहसील तिराहा, शुक्लहा, वासलीगंज, मुकेरी बाजार आदि प्रमुख चौराहों पर सोमवार को अक्सर जाम लगता है। जाम का मुख्य कारण ऑटो और ई-रिक्शा होते हैं। गौरतलब है कि ऑटो और ई-रिक्शा का रूट निर्धारित नहीं है।

मिर्जापुर शहर में करीब 8 हजार ऑटो और 12 हजार ई-रिक्शा हैं। शहर में हर दिन जाम की समस्या से लोग तंग आ चुके हैं। ऐसे में ई-रिक्शा और ऑटो के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित किए जाएंगे।

रूट निर्धारण के बाद ई-रिक्शा और ऑटो चयनित रूट पर ही चलेंगे। निर्धारित रूट पर न चलने वाले ऑटो और ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑटो यूनियन के साथ बैठक कर पूरी योजना तैयार कर ली गई है।

यातायात प्रभारी विपिन पांडेय ने बताया कि ऑटो और ई-रिक्शा को कलर कोड किया जाएगा और उन पर नंबर डाले जाएंगे। हर रूट के लिए निर्धारित रंग के साथ नंबर भी होगा। नंबर परिवहन विभाग निर्धारित करेगा, जिसमें चालक का पूरा ब्योरा होगा।

एसपी सिटी नितेश सिंह ने बताया कि शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए कलर कोडिंग के साथ नंबर की प्लानिंग चल रही है। बैठक में योजना बना ली गई है। प्रक्रिया पूरी होने और लागू होने के बाद जाम की समस्या खत्म हो जाएगी।

जीवन के लिए सबक या सिर्फ मार्क्स के लिए?

विजय गर्ग

पारंपरिक शिक्षा प्रणाली सदियों से समाज का अभिन्न अंग रही है। इसने हमारे सोचने, कार्य करने और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को आकार दिया है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय इस प्रणाली की आधारशिला हैं। वे एक संरचित वातावरण प्रदान करते हैं जहां छात्र गणित और विज्ञान से लेकर इतिहास और साहित्य तक विभिन्न प्रकार के विषय सीखते हैं। हालाँकि, कई लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क्या यह प्रणाली वास्तव में वास्तविक जीवन में मदद करती है या क्या हम केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने और प्रमाणपत्र अर्जित करने के लिए अध्ययन करते हैं। यह प्रश्न वैध है और विचारशील चर्चा का पात्र है। पारंपरिक शिक्षा को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो व्यक्तियों को भविष्य के लिए तैयार करता है। यह हमें प्रभावी ढंग से पढ़ना, लिखना और संवाद करना सिखाता है। ये बुनियादी कौशल दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, पढ़ने और लिखने का ज्ञान हमें महत्वपूर्ण जानकारी को समझने में मदद करता है, जैसे कि दवा की बोतलों पर निर्देश, सड़क के संकेत, या यहां तक कि प्रियजनों के टेक्स्ट संदेश। संचार कौशल हमें अपने विचारों और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करते हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों दोनों के लिए आवश्यक है। बुनियादी कौशल के अलावा, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें कई विषयों से परिचित कराती है। गणित हमें पैसे का प्रबंधन करने, खर्चों की गणना करने और जीवन के पैटर्न को समझने में मदद करता है। विज्ञान हमें सवाल करने, प्रयोग करने और समस्याओं का तार्किक समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। इतिहास हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ समाज कैसे विकसित हुआ है। साहित्य हमारे दिमाग को विभिन्न संस्कृतियों, भावनाओं और मानवीय अनुभवों के प्रति खोलता है। जब ये विषय प्रभावी ढंग से पढ़ाए जाते हैं, तो ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। जिस तरह से इन विषयों को पढ़ाया जाता है वह कभी-कभी वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों से कटा हुआ महसूस हो सकता है। उदाहरण के लिए, छात्र जटिल गणितीय समीकरण सीख सकते हैं लेकिन यह समझने में असफल हो जाते हैं कि वे बजट या निवेश जैसे रोजमर्रा के परिदृश्यों पर कैसे लागू होते हैं। इसी तरह, ऐतिहासिक तिथियों और घटनाओं को याद रखना अप्रासंगिक लग सकता है यदि हम मानव व्यवहार और निर्णय लेने के बारे में उनसे मिलने वाले सबक का पता नहीं लगाते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच यह अंतर पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य आलोचनाओं में से एक है। परीक्षाएँ इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनका उद्देश्य किसी छात्र की विषय वस्तु की समझ का आकलन करना है। लेकिन समय के साथ, परीक्षाएं वास्तविक सीखने की बजाय रटकर याद करने पर केंद्रित हो गई हैं। कई छात्र केवल उच्च अंक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अक्सर परीक्षा के तुरंत बाद सामग्री भूल जाते हैं। यह एक ऐसा चक्र बनाता है जहां शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करने से ग्रेड प्राप्त करने पर केंद्रित हो जाता है। ऐसे में शिक्षा का असली उद्देश्य खो जाता है। इन कमियों के बावजूद, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की अपनी खूबियाँ हैं। यह अनुशासन, समय प्रबंधन और दृढ़ता सिखाता है। छात्र एक शेड्यूल का पालन करना, असाइनमेंट पूरा करना और समय सीमा को पूरा करना सीखते हैं। ये आदतें कार्यस्थल और जीवन में मूल्यवान हैं। इसके अलावा, यह प्रणाली छात्रों को कक्षाओं में एक साथ लाकर सामाजिक कौशल को बढ़ावा देती है। वे साथियों के साथ बातचीत करना, टीमों में काम करना और रिश्ते बनाना सीखते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने और सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए ये अनुभव आवश्यक हैं।आलोचकों का तर्क है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अनुरूपता और मानकीकृत परीक्षण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है। उनका मानना है कि यह रचनात्मकता और व्यक्तिगत सोच को दबा देता है। हालाँकि इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन यह महत्वपूर्ण भी हैयह पहचानें कि सिस्टम सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक साझा मंच प्रदान करता है। यह एकरूपता सुनिश्चित करती है कि हर किसी को बुनियादी शिक्षा तक पहुंच मिले, जो एक मौलिक अधिकार है। हाल ही में शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनाने के प्रयास किए गए हैं। स्कूल व्यावहारिक शिक्षण विधियों, जैसे परियोजनाओं, प्रयोगों और वास्तविक दुनिया की समस्या-समाधान को शामिल कर रहे हैं। शिक्षकों को पाठों को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इंटरैक्टिव तकनीकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच अंतर को पाटना है। शिक्षा केवल शिक्षाविदों के बारे में नहीं है; यह हमारे मूल्यों और चरित्र को भी आकार देता है। स्कूल हमें ईमानदारी, जिम्मेदारी और सम्मान का महत्व सिखाते हैं। ये पाठ भले ही पाठ्यपुस्तकों में नहीं लिखे गए हों, लेकिन ये दैनिक बातचीत और अनुभवों के माध्यम से सिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, समूह गतिविधियों में भाग लेना हमें टीम वर्क और सहानुभूति सिखाता है। कठिन परीक्षाओं या कठिन कार्यों जैसी चुनौतियों का सामना करने से लचीलापन और आत्मविश्वास पैदा होता है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अवसरों के द्वार भी खोलती है। एक अच्छी शिक्षा एक स्थिर नौकरी हासिल करने, अच्छी आय अर्जित करने और किसी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की संभावना बढ़ाती है। यह उच्च अध्ययन और विशेष प्रशिक्षण के लिए आधार प्रदान करता है, जो कई व्यवसायों के लिए आवश्यक है। यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जिनमें रचनात्मकता और नवीनता की आवश्यकता होती है, जैसे कला या उद्यमिता, एक बुनियादी शिक्षा विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने और संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए उपकरण प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा, शिक्षा कक्षाओं और पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से आगे तक फैली हुई है। वास्तविक जीवन के अनुभव, स्वाध्याय और अन्वेषण भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, यात्रा हमें विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों के बारे में सिखाती है। स्वयंसेवा हमें सेवा और समुदाय के मूल्य को समझने में मदद करती है। शौक और रुचियों को पूरा करने से रचनात्मकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हर कोई पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में सफल नहीं होता है। कुछ लोग रचनात्मक या व्यावहारिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जिन्हें पारंपरिक कक्षाओं में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है। यह शिक्षा के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो विविध प्रतिभाओं और सीखने की शैलियों को पूरा करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, वैकल्पिक स्कूल और ऑनलाइन पाठ्यक्रम इस बात के कुछ उदाहरण हैं कि व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा को कैसे विविध बनाया जा सकता है। शिक्षा में माता-पिता और समाज की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माता-पिता अपने बच्चों की सीखने की यात्रा का मार्गदर्शन और समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जिज्ञासा को प्रोत्साहित कर सकते हैं, संसाधन प्रदान कर सकते हैं और सीखने के लिए अनुकूल माहौल बना सकते हैं। समाज की भी जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा को महत्व दे और उन पहलों का समर्थन करे जो इसे सभी के लिए सुलभ बनायें। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में खामियां हैं, लेकिन यह कई लाभ भी प्रदान करती है। यह हमें आवश्यक कौशल, ज्ञान और मूल्यों से सुसज्जित करता है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि कभी-कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि हम केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो सबक सीखते हैं उसका अक्सर हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मुख्य बात यह है कि शिक्षा को खुले दिमाग से अपनाया जाए और हम जो सीखते हैं उसे सार्थक तरीकों से लागू करने की इच्छा रखें। पारंपरिक शिक्षा की शक्तियों को नवीन तरीकों और वास्तविक दुनिया के अनुभवों के साथ जोड़कर, हम एक ऐसी प्रणाली बना सकते हैं जो वास्तव में व्यक्तियों को जीवन के लिए तैयार करती है।

एक विद्वान और दो चालाक बच्चे

विजय गर्ग

एक बार नयासर गाँव के दस बारह साल के दो शरारती बच्चों ने एक आदमी की परीक्षा लेना तय किया। ऐसे मुश्किल प्रश्न पूछना इन बच्चों ने तय किया जिनका उत्तर देना उसे कभी भी संभव नहीं होगा. बहुत सोच विचार कर इन दो बच्चों ने तीन प्रश्न ढूंढ़ निकाले। इन बच्चों ने तय किया कि हम एक छोटी चिड़िया को पीठ के पीछे पकड़कर उससे पूछें, हमारे हाथ में क्या है? वह बूढ़ा आदमी जवाब देगा, 'पक्षी है'. 'लेकिन यह कोई मुश्किल सवाल नहीं हुआ, वे लड़के एक दूसरे से बोले.

इसके बाद दूसरा प्रश्न हम यह पूछेगे, हमारे हाथ में कौन सा पक्षी है? वह कहेगा,

चिड़िया है. लेकिन यह भी आसान सवाल है', वे दोनों फिर एक ।से बोले. लेकिन इसके बाद का तीसरा प्रश्न निश्चित ही इम्तहान लेने वाला होगा. इसके बाद हम पूछेंगे, यह चिड़िया जीवित है या मरी हुई है?

अब अगर नवनीत उसने जवाब दिया कि मरी हुई है तो जवाब गलत होगा, क्योंकि चिड़िया तो जीवित रहेगी. और अगर उसने कहा कि जीवित है तो फिर जवाब गलत होगा. क्योंकि तब हम उस चिड़िया को वहीं के वहीं दबा कर मार डालेंगे. दोनों बहुत प्रसन्न हुए. क्योंकि उन्हें प्रश्न ही ऐसा मिला था जिसका कोई भी उत्तर गलत होने वाला था।

फिर एक छोटी सी चिड़िया लेकर ये बच्चे उस वृद्ध आदमी के पास पहुँचे. और तयशुदा तरीके से पीठ के पीछे हाथ रखकर उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, 'हमारे हाथ में क्या है?' उस आदमी ने तुरंत बताया, 'पक्षी है।

उत्तर सुनकर बालको को अचरज नहीं हुआ. उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, 'कौन सा पक्षी?' तुरंत उत्तर मिला, 'चिड़िया है'. इस उत्तर ने भी लड़कों को चकित नहीं किया। क्योंकि उन्हें पूछना था तीसरा प्रश्न और उसी प्रश्न का उत्तर सुनना था. फिर लड़कों ने पूछा, हमारे हाथ की यह चिड़िया मरी हुई है या ज़िंदा?"

पहले दो प्रश्नों के उत्तर तुरंत देने वाला वह अनुभवी आदमी इस बार थोड़ा सा रुका - शायद सोचने के लिये. फिर बोला, वह तुम्हारे हाथ में है। वह वृद्ध आदमी अनुभव से बोल रहा था. उसे मालूम था कि चिड़िया को मारना या जिंदा रखना उन लड़कों के ही हाथ में था!!

यहां उस वृद्ध आदमी की विकेक और ज्ञान का पता चलता है और हमारे अपने जीवन मे भी लगभग सारी चीजे हमारे ही हाथो में तो रहती है लेकिन हम अपने आप को किस तरह बनाना चाहते है और हम अपना आने वाला कल, आज से ही कैसे तैयार कर सकते है ये सब ₹ हमारे हाथ मे ही है

शादियों और पार्टियों में दिखावा

विजय गर्ग

विवाह समारोहों के माध्यम से स्वयं को दूसरों से बड़ा, योग्य, सक्षम और आकर्षक बनाने की यह अंधी दौड़ निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है। उधार का घी पीकर अपनी खुशी जाहिर करने की प्रवृत्ति निश्चित रूप से व्यक्ति, परिवार और समाज के पतन का कारण बन रही है। वर्तमान की चार दिवसीय चमक भविष्य को गहरे अंधकार में धकेल रही है। देश में कोरोना की कम होती रफ्तार और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में दी गई छूट के कारण अब जन जीवन सामान्य होता दिख रहा है। सहज रूप मेंवैवाहिक कार्यक्रमों की रौनक लौट आई है। अब पहले जैसी भीड़ लगती है. हाल ही में देवसानी एकादशी के बाद जब विवाह की प्रक्रिया शुरू हुई तो मुझे भी एक के बाद एक कई शादियों में शामिल होने का मौका मिला। इस भव्य शादी में हमेशा की तरह वैभव और आराम की भी झलक थी। 'तेरी कमीज, मेरी कमीज से सीधे ऐसे' की तर्ज पर चल रहे इस कार्यक्रम में आयोजक अपनी क्षमता से ज्यादा पैसे खर्च करते नजर आए। गार्डन, धर्मशाला, लॉज-होटल जैसे विवाह स्थलों की रौनक बढ़ाना चाहते हैंइसके चलते टेंट और बिजली उपकरणों पर पैसा पानी की तरह बहता नजर आया. कार्यक्रम पंडाल की सजावट बढ़िया है, खान-पान को अपना हुनर दिखाने का ज़रिया बनाया गया है. खाने में कुछ नया या नई वैरायटी परोसने की होड़ में बनाए गए व्यंजनों की संख्या छब्बीस से भी ज्यादा खुशी से भरी देखी गई। अब यदि खाने वाला चार-पांच से अधिक व्यंजन चखता या थाली में छोड़ता नजर न आए तो प्रबंधकों की आर्थिक समृद्धि बता दी जाती है। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे विवाह समारोहों में पैसा भी और खाना भीयह बर्बाद हो गया है. क्या आपको लगता है कि क्या कोई मेहमान खाने की बर्बादी रोक पाएगा? यदि वह समझदारी दिखाए कि इतने सारे व्यंजनों में से कुछ का स्वाद न चखे या प्रत्येक प्लेट से आधा निवाला, भले ही कुछ मात्रा में ही क्यों न ले, भोजन का बर्बाद होना निश्चित है। हालाँकि, हमारे मेहमानों से इतने विवेक की अपेक्षा करना अनुचित होगा। जब से हमारे देश में 'अपशिष्ट संस्कृति' का प्रसार हुआ है तब से भोजन की बर्बादी भी बढ़ गई है। पुरानी संस्कृति की बुराई जैसी कोई चीज़ नहीं है. कमी सिर्फ हममें है, इसके सही ढंग से काम करने कीये संस्कार यहां नहीं पनपे. शादी समारोहों में अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी थाली में ज्यादा से ज्यादा खाने-पीने की चीजें यह सोच कर रख लेते हैं कि बाद में मिल जाएगी या फिर थाली में ही छोड़ देंगे, लेकिन बाद में ज्यादातर लोग इसे यूं ही रख देते हैं। जैसे यदि छब्बीस या उससे अधिक व्यंजन बनाए जाएं तो भोजन की बर्बादी को कौन रोक सकता है? हमारी संस्कृति में हर अनाज का अपना महत्व है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है, इसे ईश्वर तुल्य माना गया है। ऐसी स्थिति में विवाहआयोजनों में जूठन कह कर खाना फेंकना क्या खाने का अपमान या भगवान का अपमान नहीं है? हम चीजों की नकल करने में माहिर हैं. उस अनुकरण में बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल न करें। यह दावतों या दावतों में दिखावे का नतीजा है। अगर नकल करनी ही है तो सिर्फ उन्हीं देशों में की जानी चाहिए जहां खाने की बर्बादी को लेकर सख्त कानून हैं. कई देशों में भोजन की बर्बादी पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। पहले जब लोगों को जमीन पर बैठकर खाना परोसने का रिवाज था, तब इतना खाना बर्बाद नहीं होता था. लेकिन हम वो परंपराछोड़ दिया है हमें भोजन की बर्बादी की इस होड़ से समाज को बचाना है और हम ऐसा कर पाएंगे या समाज को संदेश तभी दे पाएंगे जब हम इसकी शुरुआत खुद से करेंगे। बेहतर होगा कि हम अपने परिवार में शादी समारोह सादगी और भव्यता के साथ आयोजित करें और शादी समारोह के चकाचौंध खर्चों से जोड़े के भविष्य को उज्ज्वल करें।

● स्क्रीन से परे

डिजिटल युग में, यूट्यूब सीखने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है, खासकर उच्च प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। पारंपरिक शिक्षा मॉडल, जो अक्सर महंगे कोचिंग संस्थानों पर निर्भर होता है, को पूरक बनाया जा रहा है और, कुछ मामलों में, इसे ऑनलाइन उपलब्ध मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। हालाँकि, जबकि यूट्यूब शिक्षा तक अभूतपूर्व पहुँच प्रदान करता है, यह बदलाव ऐसी चुनौतियाँ भी लाता है जिनका छात्रों और शिक्षकों को समाधान करने की आवश्यकता है। लचकीले लगभग हर विषय और टॉपिक को कवर करने वाले लाखों शैक्षिक वीडियो के साथ, छात्र अब अपनी गति से, कभी भी, कहीं भी सीख सकते हैं। यह लचीलापन भारत की दो सबसे प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं जेईई और एनईईटी की तैयारी करने वालों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है।

यूट्यूब व्यापक पाठ्यक्रम, परीक्षण रणनीतियाँ और समस्या समाधान सत्र प्रदान करता है जिसके लिए पहले कोचिंग संस्थानों में पर्याप्त वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती थी। हालाँकि, सामग्री की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में काफी भिन्नता होती है। विनियमित संस्थानों के विपरीत, यूट्यूब में निगरानी का अभाव है, जिसका अर्थ है कि छात्रों को जो देखना है उसका चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जबकि कुछ प्लेटफ़ॉर्म संरचित और व्यापक सामग्री प्रदान करते हैं, अन्य सटीकता या स्पष्टता की कमी के कारण छात्रों को भ्रमित या गलत जानकारी दे सकते हैं। जबकि कई शिक्षकों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के लिए व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए यूट्यूब को अपनाया है, लेकिन वे सभी छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और प्रत्यक्ष परामर्श की कमी है, जो पारंपरिक कोचिंग केंद्र प्रदान करते हैं। लाइव कक्षा सेटिंग में, संदेहों को वास्तविक समय में स्पष्ट किया जाता है, और व्यक्तिगत ध्यान छात्रों को ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है; कुछ पूर्व रिकॉर्ड किए गए यूट्यूब वीडियो पूरी तरह से दोहराए नहीं जा सकते। यूट्यूब की लोकप्रियता के प्रमुख चालकों में से एक इसकी सामर्थ्य है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को मुफ्त में शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देता है।

इसने खेल के मैदान को समतल कर दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कभी गुणवत्तापूर्ण कोचिंग केंद्रों तक पहुंच नहीं थी। हालाँकि, केवल सामर्थ्य ही सफलता की गारंटी नहीं देती। यूट्यूब की ओर रुख करने वाले कई छात्र संघर्ष करते हैं अध्ययन के लिए संरचित योजनाओं, अनुशासन और जवाबदेही की अनुपस्थिति के साथ। शिक्षकों और सहपाठियों के बाहरी दबाव के बिना, कुछ लोगों को प्रेरित और सुसंगत बने रहना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी और उपयुक्त डिवाइस जैसे कारकों पर निर्भर है; ऐसे विशेषाधिकार जो प्रत्येक छात्र वहन नहीं कर सकता, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में। बातचीत का अभाव यूट्यूब अपने एल्गोरिदम के माध्यम से वैयक्तिकरण प्रदान करता है, उपयोगकर्ता के व्यवहार के आधार पर वीडियो की अनुशंसा करता है।

छात्र अपनी सीखने की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, कठिन विषयों पर दोबारा विचार कर सकते हैं या आवश्यकतानुसार आगे बढ़ सकते हैं। कुछ शिक्षक कक्षा जैसी बातचीत का अनुकरण करते हुए, लाइव सत्रों के माध्यम से या टिप्पणियों में छात्रों के साथ जुड़ते हैं। हालाँकि, जब गहन, अधिक वैयक्तिकृत संदेह समाधान की बात आती है तो बातचीत का यह स्तर अक्सर अपर्याप्त होता है। साथ ही, यूट्यूब इंटरैक्शन में आमतौर पर देरी होती है, और प्रतिक्रियाएं सीमित हो सकती हैं। यह एक बड़ी कमी हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो जटिल विषयों की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत फीडबैक पर भरोसा करते हैं। हालाँकि यूट्यूब ने शिक्षा का लोकतंत्रीकरण किया है, लेकिन इसके संभावित नुकसानों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

मुफ़्त सामग्री की प्रचुरता उन छात्रों के लिए भारी पड़ सकती है जो नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें या अपनी शिक्षण सामग्री कैसे तैयार करें। प्लेटफ़ॉर्म की खुली प्रकृति का मतलब है कि सभी सामग्री खुली नहीं हैसटीक या अद्यतन, संभावित रूप से भ्रम या यहां तक कि गलत सूचना का कारण बनता है। इसके अलावा, यूट्यूब की स्व-चालित प्रकृति विलंब और अनुशासन की कमी का कारण बन सकती है, क्योंकि इसके लिए महत्वपूर्ण आत्म-प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जो छात्र समय प्रबंधन के साथ संघर्ष करते हैं वे बिना इसका एहसास किए ही पिछड़ सकते हैं। इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण जो यूट्यूब की सुविधा को अधिक संरचित, वैयक्तिकृत शिक्षण के साथ जोड़ता है, आगे बढ़ने का सर्वोत्तम मार्ग प्रदान कर सकता है।

डिजिटल क्राइम से हो रहा मानवाधिकार उल्लंघन

हालांकि सरकार द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 1930 और रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं और कितनी का निपटारा होता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है

समाज में बह रहे सूचनाओं के प्रवाह में हर दूसरी खबर मनुष्यता के अधिकारों के हनन से संबंधित होती है। यह समस्या एक देश, एक समाज एवं वर्ग विशेष की नहीं, बल्कि विश्वभर में रह रहे हर मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। आज जो आर्थिक एवं डिजिटल तौर पर सक्षम है, वो सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तौर पर कमजोर वर्ग को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वैश्विक स्तर पर इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध एवं यूक्रेन व रूस युद्ध के मूल कारणों पर चर्चा की जाए तो मूल कारण नियंत्रण ही है। लेकिन इस नियंत्रणकारी नीति का खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है, जो शायद पूरी तरह से युद्ध के कारणों व परिस्थितियों से रूबरू भी नहीं है। इस परिस्थिति में आम जनता के अधिकार विनाशकारी तरीके से रौंद दिए जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों ने मानव अधिकारों के महत्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अहम मुद्दा बना दिया था। इसी गंभीरता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। इसलिए हर वर्ष यह दिन विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भेदभाव से आजादी का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भोजन का अधिकार आदि शामिल हैं जो व्यक्ति को समाज में हक एवं बिना किसी दबाव के जीने का अधिकार देते हैं।

इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम हमारे अधिकार, हमारा भविष्य रखी गई है। इसी के अंतर्गत डिजिटल सुरक्षा अधिकार को भी जोड़ा जाना चाहिए। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। लेकिन इन अधिकारों की अनुपालना व अवहेलना सब परिस्थितियों के हिसाब से हो रही है जो वाकई में चिंता का विषय है। वर्तमान में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम तो किया जा रहा है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन की कमी के कारण बढ़ती डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं ने मानवीय अधिकारों के भविष्य पर व्यापक चर्चा शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में व्यापक चर्चा कर चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट एक नया धोखाधड़ी करने का तरीका है जिसमें कोई अफसर बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से किसी भी धोखाधड़ी में फंसाकर रुपयों की मांग करता है। यह धोखाधड़ी शहरों से लेकर गांवों तक हर वर्ग में पहुंच चुकी है। हद तो तब हो गई जब पढ़ा-लिखा वर्ग भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहा है। अभी हाल में ही नोएडा में सेवानिवृत्त मेजर जनरल को उनके नाम पर भेजे गए पार्सल में ड्रग्स होने की जांच के नाम पर पांच दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर दो करोड़ की ठगी, सोनीपत में सेवानिवृत्त अधिकारी को व्हाट्सऐप पर नकली वारंट भेजकर डिजिटल अरेस्ट कर सरकारी खाते बताकर 1.78 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये संख्या बहुत लंबी है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2020 से 2024 तक 582000 केस के अंतर्गत 3207 करोड़ के धोखाधड़ी मामलों की जानकारी है, यानी कि कई हजार केस तो पंजीकृत या प्रकाश में ही नहीं आए। वर्तमान में रुपयों का लेन-देन काफी हद तक डिजिटल हो चुका है। ऐसे में साइबर अपराध के माध्यम से मानवाधिकारों को सुरक्षित करना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। जहां वर्ष 2014 में देश में 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, जो 2024 में बढ़कर 95 करोड़ हो चुके हैं। दुनिया भर के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 46 प्रतिशत वर्तमान में भारत में हो रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में ठगों की नजर सीधा बैंक खातों पर रहती है। हालांकि सरकार द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 1930 और रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

लेकिन कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं और कितनी का निपटारा होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के समय में डिजिटल तकनीक के माध्यम से मानवाधिकार हनन एक ज्वलंत मुद्दा है। इससे बचने का एकमात्र उपाय जागरूकता ही है। व्यक्तिगत तौर पर स्वयं भी और अपने आसपास साइबर अपराध से बचने के तरीकों को जानिए और बताइए सामाजिक स्तर पर फैल रही ज्वलंत फेक न्यूज, साइबर अपराध, सरकारी मशीनरी की जानकारी, कानून और विशेषकर ठगी होने पर शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। सरकार को भी चाहिए कि टेलिकॉम ऑपरेटर और बैंकिंग सिस्टम को भी उपभोक्ताओं के निजी डाटा के प्रति जवाबदेह बनाएं ताकि अपराध होने पर ठगी करने वाला और जिस माध्यम से हो रहा है, दोनों को सजा दी जाए। देश के स्तर पर सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के जरिए फैल रहे साइबर अपराध व साइबर युद्ध के लिए अलग और समय पर सिस्टम तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में दिखने वाले मानवीय नुकसान ने मानवाधिकारों की चर्चा हुई, लेकिन अगला युद्ध साइबर युद्ध होगा जो अदृश्य होकर कमजोर राष्ट्र, समाज और वहां रहने वाले लोगों पर हमला करेगा। इस हमले से लडने के लिए समाज के हर व्यक्ति को तैयार करना होगा, क्योंकि मानवाधिकारों की सुरक्षा डिजिटल कत्र्तव्य से जुड़ी हुई है। एक और चिंता का विषय भी है। भारत में मानवाधिकार संगठनों की सक्रियता खास तौर से पंजाब के आतंकवाद के भयावह दौर से देखी जा रही है। जब इन संगठनों को पुलिस व सेना के जवानों का हर छोटा-बड़ा कारनामा तो नजर आता था, लेकिन आतंकवादियों की करतूतों के विरुद्ध इनकी जुबान पर लगाम कसी रहती थी। इसके बारे में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एएस आनंद ने एक बार कठोर टिप्पणी करते हुए कहा भी था कि ये संगठन सुरक्षा बलों के अत्याचारों पर तो उंगली उठाते हैं, पर आतंकवादी संगठन कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, उस पर चुप रहते हैं।

यह हकीकत भी है कि यदि कोई आतंकवादी या शरारती तत्व पुलिस अथवा सेना के हाथों मारे जाएं तो मानवाधिकारवादी संगठन खूब हो-हल्ला मचाते हैं लेकिन वहीं अगर यही सिरफिरे लोग निर्दोषों के लहू से होली खेलें, अबलाओं की इज्जत के सरेआम चिथड़े उड़ाएं, उन्हें गैंगरेप जैसी पाश्विक घटनाओं को अंजाम देकर जिंदा जला डालें, तो ऐसी हैवानियत मानवाधिकार के ठेकेदारों को नजर नहीं आती, बल्कि ऐसे मामलों में इन संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाने वालों के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आतंकवादी संगठन किसी स्थापित कानून के तहत काम करने वाली कोई सरकारी संस्था नहीं हैं और वैसे भी आतंकवादी संगठनों की कार्रवाई चूंकि कानून की नजर में अपराध है, अतः यदि कोई आतंकवादी या अराजक तत्व पकड़ा भी जाए, तब उसके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मानवाधिकार संगठनों की भूमिका हर मामले में ही संदेहास्पद रही हो बल्कि कई मामलों में इन संगठनों ने सही मायनों में पीड़ित मानवता के हित में सार्थक पहल की है, किन्तु यह भी कटु सत्य है कि दुनियाभर में आज भी करोड़ों-अरबों लोग मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के 76 वर्षों बाद भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए 1961 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनियाभर में करीब 120 देशों में मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। भारत में सितंबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों का संरक्षण करना और उनको प्रोत्साहन देना ही था। इसके बावजूद मानवाधिकार संरक्षण के लिए ठोस नीति की जरूरत है।

शक्तिकांत दास का कार्यकाल खत्म, बोले- जीडीपी ग्रोथ सुस्त होने की वजह रेपो रेट में कटौती नहीं

परिवहन विशेष न्यूज

आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात से साफ इनकार किया कि उनके कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों में रेपो रेट में कटौती नहीं किये जाने की वजह से देश की आर्थिक विकास दर में हाल ही में सुस्ती देखने को मिली है। डॉ. दास ने लंबे समय तक गवर्नर पद पर सेवा का अवसर देने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया।

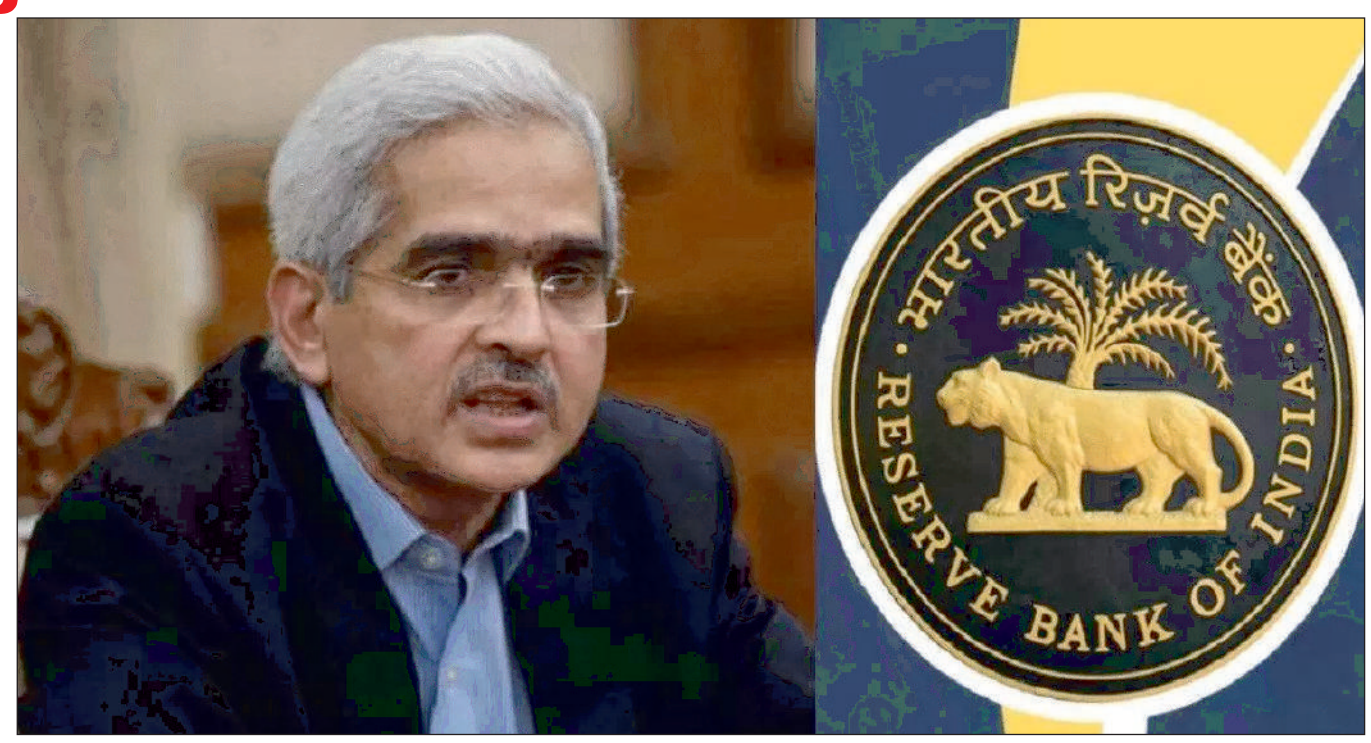

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक गवर्नर पद पर छह वर्षों तक अपनी सेवा देने वाले डॉ. शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों को लेकर केंद्र सरकार व केंद्रीय बैंक के बीच किसी तरह की संवादहीनता या तनाव की संभावनाओं से साफ तौर पर इनकार किया है। डॉ. दास का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हुआ और इस दिन उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस करके अपनी सेवा के दौरान की चुनौतियों व अवसरों और बुधवार (11 दिसंबर, 2024) से गवर्नर पर पर आसीन होने वाले संजय मल्होत्रा की चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात की।

उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि उनके कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों में रेपो रेट में कटौती नहीं किये जाने की वजह से देश की आर्थिक विकास दर में हाल ही में सुस्ती देखने को मिली है। सोशल मीडिया एक्स पर भावनात्मक तौर पर लिखे गये पोस्ट में डॉ. दास ने लंबे समय तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पर सेवा का अवसर देने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही आरबीआई के सभी सहयोगियों का आभार जताया।

दास ने कहा "केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार कई मुद्दों पर अलग-अलग विचार रखते हैं और यह कोई नई बात नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान इस तरह के कई मुद्दों का समाधान आंतरिक विमर्श से किया है।" उन्होंने ब्याज दरों को लेकर केंद्र व आरबीआई के बीच समन्वय को बेहतरीन करार दिया। यहां बता दें कि दास से पहले के लगातार दो आरबीआइ गवर्नर डॉ. रघुराम राजन और डॉ. उर्जित पटेल के साथ केंद्र सरकार के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे।

उर्जित पटेल के साथ केंद्र सरकार का विवाद इतना बढ़ गया था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। राजन को भी बीजेपी सरकार ने वर्ष 2016 में कार्य विस्तार नहीं दिया था। बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक में सरकार के साथ अपने मतभेदों के बारे में विस्तार से लिखा था।

पिछले हफ्ते जब आरबीआई ने लगातार 11वीं मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक में रेपो रेट में कटौती नहीं की तो यह कहा गया कि केंद्र सरकार की चाहत के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है। दरअसल, हाल के हफ्तों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्याज दरों में कटौती की जरूरत बताई थी।

सोशल मीडियाा साइट एक्स पर डॉ. दास ने मंगलवार को लिखा "आरबीआई गवर्नर के तौर पर देश की सेवा करने का अवसर देने के लिए और लगातार दिशानिर्देश व प्रोत्साहन देने के लिए मैं पीएम नरेन्द्र मोदी का आभारी हूं। वित्तमंत्री सीतारमण को भी उनके लगातार समर्थन के लिए तहेदिल से धन्यवाद। राजकोषीय व मौद्रिक नीति का समन्वयन बहुत ही बढ़िया रहा है और इसकी वजह से पिछले छह वर्षों के दौरान कई बड़ी चुनौतियों का हमने सफलतापूर्वक सामना किया। पूरी आरबीआई टीम का धन्यवाद जिनकी वजह से हमने बेहद अप्रत्याशित वैश्विक चुनौतियों के काल में भी सफलतापूर्वक

2025 में कैसी रहेगी जीडीपी ग्रोथ, क्या है इकोनॉमी के लिए चिंता की बात?

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले हफ्ते RBI ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा लेकिन सिस्टम में लिक्विडिटी डालने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 50 आधार अंकों की कटौती की। भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। एसएंडपी का कहना है कि इसके मुकाबले सितंबर तिमाही की 5.4 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से काफी कमजोर रही।

नई दिल्ली। भारतीय उपभोक्ता लंबे समय से ब्याज दरों में कटौती का इंतजार कर रहे हैं। आरबीआई ने फरवरी 2023 से ब्याज दरों को 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा है। सरकार ने संजय मल्होत्रा को नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया है। इससे फरवरी 2025 की एमपीसी में रेपो रेट में कटौती की संभावना बढ़ गई है।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स का भी मानना है कि आरबीआई मौद्रिक नीति में 'मामूली ढील' दे सकता है। एसएंडपी के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में ₹मजबूत वृद्धि₹ के लिए तैयार है और मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आने का अनुमान है। इससे आरबीआई रेपो रेट में कटौती करेगा। S&P ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.8 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में 6.9 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान है।

S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अर्थशास्त्री विश्रुत राणा ने कहा, ₹मजबूत शहरी खपत, स्थिर सेवा क्षेत्र की वृद्धि और बुनियादी ढांचे में चल रहे निवेश की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में मजबूत वृद्धि के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आने पर केंद्रीय बैंक 2025 के दौरान मौद्रिक नीति में मामूली ढील देगा।₹

सितंबर तिमाही की जीडीपी ग्रोथ निराशाजनक

पिछले हफ्ते RBI ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा, लेकिन सिस्टम में लिक्विडिटी डालने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 50 आधार अंकों की कटौती की। भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। एसएंडपी का कहना है कि इसके मुकाबले सितंबर तिमाही की 5.4 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से काफी कमजोर रही।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता के कारण

राजकोषीय खर्च के सुस्त पड़ने का ओवरऑल असर इकोनॉमी पर दिख रहा है। शहरी मध्यम वर्ग ने भी गैरजरूरी खर्च कम कर दिया है। इससे शहरी खपत भी कमजोर पड़ गई है। इसी की झलक सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर दिखी। एसएंडपी का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में सुस्ती हमारे अनुमान के लिए जोखिम पैदा करती है।

अर्थव्यवस्था के लिए कई और भी चुनौतियां हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र और घरेलू बैलेंस शीट में महामारी के बाद की कमजोरी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक विनिर्माण वातावरण और कृषि क्षेत्र की कमजोर वृद्धि शामिल हैं।

नए RBI गवर्नर कब देंगे ब्याज दरों में कटौती का तोहफा, इकोनॉमी पर क्या होगा असर; जानें पूरी डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले हफ्ते RBI ने मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा लेकिन सिस्टम में लिक्विडिटी डालने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 50 आधार अंकों की कटौती की। अब संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त हो गए हैं और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी बढ़ गई है। आइए जानते हैं कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा।

नई दिल्ली। भारतीय उपभोक्ता लंबे समय से नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का इंतजार कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री भी केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में कटौती सलाह दे चुके हैं, ताकि सुस्त पड़ती इकोनॉमी में नई जान फूंकी जा सके। आरबीआई ने फरवरी 2023 यानी करीब दो साल से ब्याज दरों को 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा है।

सरकार ने संजय मल्होत्रा को नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया है। इससे फरवरी 2025 की एमपीसी में रेपो रेट में कटौती की संभावना बढ़ गई है। संजय मल्होत्रा बतौर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह ले रहे हैं, जिनका अधिक फोकस महंगाई को काबू करने के साथ रुपये में गिरावट रोकने पर था।

फॉरेक्स ट्रेडर्स यानी विदेशी मुद्रा के व्यापारियों का भी मानना है कि नया आरबीआई गवर्नर बनने से ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। यही वजह है कि आज यानी 10 दिसंबर (मंगलवार) को डॉलर के मुकाबले रुपया नए ऑल टाइम लो-लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि, इसमें बाद में रिकवरी हुई। एक डॉलर की कीमत अब 84.85 रुपये है। यह सोमवार के बंद भाव के मुकाबले 1 पैसे की तेजी दर्शाता है।

क्या कह रहे हैं विदेशी मुद्रा व्यापारी?

विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि शक्तिकांत दास के जाने से अनिश्चितता आई है, क्योंकि उनके कार्यकाल में ऐसी नीतियां अपनाई गई थीं, जिनसे रुपये में बड़ी गिरावट नहीं आई। सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के एमडी अमित पबारी ने कहा, "राजस्व संबंधी चिंताओं पर आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले संजय मल्होत्रा के रुख ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं।"

अर्थशास्त्रियों का रेट कट पर राय

अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि शक्तिकांत दास के जाने से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में नरम रुख आ सकता है। दास और डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा 6 मेंबर वाले पैनल में ब्याज दरों में कटौती के सबसे मुखर विरोधी थे। उनक फोकस महंगाई कम करने और रुपये को गिरने से बचाने पर था। लेकिन, दास का कार्यकाल खत्म हो चुका है और पात्रा का भी जनवरी के मध्य में खत्म होने वाला है। ऐसे में फरवरी की एमपीसी में रेट कट की गुंजाइश काफी ज्यादा बढ़ जाती है।

S&P का रेट कट पर क्या है अनुमान?

दुनिया की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स का भी मानना है कि आरबीआई मौद्रिक नीति में 'मामूली ढील' दे सकता है। एसएंडपी के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में ₹मजबूत वृद्धि₹ के लिए तैयार है और मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आने का अनुमान है। इससे आरबीआई रेपो रेट में कटौती करेगा। S&P ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.8 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में 6.9 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान है।

नवंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14 प्रतिशत घटा, क्या है इसकी वजह?

विभिन्न व्यापक आर्थिक कारकों भू-राजनीतिक घटनाओं और अमेरिकी चुनाव परिणामों के कारण अस्थिरता बढ़ गई। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में निवेशकों ने निवेश करते समय प्रतीक्षा और निगरानी का रुख अपनाया। इस प्रकार नवंबर 2024 के लिए एसआइपी के जरिये मासिक योगदान लगभग स्थिर रहा वहीं एकमुश्त प्रवाह में गिरावट आई। आइए जानते हैं नवंबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पूरा हाल।

नई दिल्ली। इक्विटी म्यूचुअल फंड में नवंबर में मासिक आधार पर 14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 35,943 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। विभिन्न व्यापक आर्थिक कारक, भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी चुनाव के परिणाम से उत्पन्न अस्थिरता इसकी मुख्य वजह रही।

हालांकि, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, गिरावट के बावजूद यह शेयरों में निवेश करने वाले कोषों में शुद्ध प्रवाह का लगातार 45वां महीना है, जो निवेशकों के बीच म्यूचुअल फंड के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। इसके अलावा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिये नवंबर में मासिक योगदान पिछले महीने 25,320 करोड़ रहा। अक्टूबर में यह आंकड़ा 25,323 करोड़ रुपये था।

मोतीलाल ओसवाल एएमसी के अखिल चतुर्वेदी ने कहा, 'विभिन्न व्यापक आर्थिक कारकों, भू-राजनीतिक घटनाओं और अमेरिकी चुनाव परिणामों के कारण अस्थिरता बढ़ गई। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में निवेशकों ने निवेश करते समय प्रतीक्षा और निगरानी का रुख अपनाया। इस प्रकार नवंबर 2024 के लिए एसआइपी के जरिये मासिक योगदान लगभग स्थिर रहा वहीं एकमुश्त प्रवाह में गिरावट आई।'

कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड उद्योग में समीक्षाधीन महीने में 60,295 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जबकि अक्टूबर में यह 2.4 लाख करोड़ रुपये था। वहीं उद्योग की प्रबंधन अधीन शुद्ध परिसंपत्तियां पिछले महीने बढ़कर 68.08 लाख करोड़ रुपये हो गईं, जो अक्टूबर में 67.25 लाख करोड़ रुपये थी। आंकड़ों के अनुसार, शेयरों में निवेश वाली योजनाओं में अक्टूबर में 41,887 करोड़ रुपये की तुलना में नवंबर में 35,943 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।

गोल्ड ईटीएफ श्रेणी 1,257 करोड़ रुपये का निवेश

नवंबर में गोल्ड ईटीएफ श्रेणी में 1,257 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ, जो पिछले महीने के 1,961 करोड़ रुपये से कम है। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर-मैनेजर रिसर्च हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, 'अक्टूबर की तुलना में जुटाया गया फंड कम रहा, लेकिन भुनाए गए फंड की संख्या अधिक रही। इसका मतलब है कि निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर सोने के कारोबार और आसन्न विवाह सीजन के साथ मुनाफावसूली का विकल्प चुना होगा, क्योंकि भौतिक सोने की मांग अधिक है।'

पिछले कुछ समय में सोने और चांदी की डिमांड में काफी अधिक तेजी आई है। इसका असर दोनों धातुओं की कीमतों पर भी देखा जा सकता है।

11 दिसंबर से खुलेगा मेगा मार्ट का आईपीओ, जानिए प्राइस बैंड समेत पूरी डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

विशाल मेगा मार्ट का 11 से 13 दिसंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकेगा। विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 1025641025 शेयरों की ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत बिक्री होगी। कंपनी ने आईपीओ के लिए 74-78 रुपये का प्राइस बैंड तय कर रखा है। इसका लॉट साइज 190 शेयर का होने वाला है।

नई दिल्ली। विशाल मेगा मार्ट का 8,000 करोड़ का आईपीओ ला रही है। इसे 11 से 13 दिसंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकेगा। यह इश्यू ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। इसका मतलब है कि आईपीओ का पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा। ग्रे मार्केट में विशाल मेगा मार्ट आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, इसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी जुड़े हैं, जिन पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए।

Vishal Mega Mart IPO

विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 1,025,641,025 शेयरों की ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत बिक्री होगी। कंपनी ने आईपीओ के लिए 74-78 रुपये का प्राइस बैंड तय कर रखा है। इसका लॉट साइज 190 शेयर का होने वाला है। शेयर अलॉटमेंट 16 दिसंबर को फाइनल होगा। इसकी बीएसई और एनएसई पर एंट्री 18 दिसंबर को होगी। इस इश्यू का रजिस्ट्रार केफिन टेक है।

विशाल मेगा मार्ट IPO GMP

विशाल मेगा मार्ट आईपीओ को ग्रे मार्केट में ठीक-ठाक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस मौजूदा जीएमपी 25 रुपये है। इसका मतलब है कि आईपीओ निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब 25 रुपये यानी 32.05 फीसदी का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ग्रे मार्केट एक अनधिकृत बाजार है, जहां लिस्टिंग से पहले शेयरों की खरीद-बिक्री होती है। एक्सपर्ट का मानना है कि निवेश से पहले जीएमपी से अधिक फंडामेंटल पर ध्यान देना चाहिए।

शिाल मेगा मार्ट क्या करती है?

विशाल मेगा मार्ट (VMM) देश की बड़ी रिटेल चेन में शुमार है। इसका फोकस मध्यम और निम्न-मध्यम आय वर्ग के ग्राहकों पर रहता है। विशाल मेगा मार्ट के प्रोडक्ट तीन प्रमुख कैटेगरी में आते हैं। परिधान, सामान्य सामान और फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG)। यह कंपनी जून तिमाही तक देश में 626 विशाल मेगा मार्ट स्टोर चला रही थी। इसका अपना मोबाइल ऐप और साइट भी है।

इस बात का रखें ध्यान

विशाल मेगा मार्ट, सब्सिडियरीज, प्रमोटर्स और निदेशकों के खिलाफ कई कानूनी कार्यवाही चल रही है। इसमें से एक आपराधिक मामला है। आरएचपी के मुताबिक, साथ ही 16 टैक्स प्रक्रियाएं और 32 अन्य कानूनी या नियामक मामले हैं। सब्सिडियरीज के खिलाफ 7 आपराधिक मामले, 33 टैक्स मुकदमे और 247 कानूनी एक्शन चल रही हैं। विशाल मेगा मार्ट के प्रमोटरों के खिलाफ चार टैक्स मुकदमे भी चल रहे हैं।

संजय मल्होत्रा के आरबीआई गवर्नर बनने पर शेयर बाज़ार ने कैसी प्रतिक्रिया दी, रुपये का क्या है हाल?

संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा जिसकी शुरुआत 11 दिसंबर से होगी। मल्होत्रा की नियुक्ति पर शेयर बाजार और करेंसी मार्केट ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है।

नई दिल्ली। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। मल्होत्रा की नियुक्ति पर शेयर बाजार ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है।

सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट आई, लेकिन यह जल्द ही रिकवर हो गया। विदेशी फंडों के ताजा प्रवाह और एशियाई बाजारों में तेजी ने भी बाजारों की वापसी में योगदान दिया। वहीं, रुपये की बात करें, तो यह डॉलर के मुकाबले 8 पैसे मजबूत हुआ है।

बैंकिंग शेयरों में दिख रही तेजी

मंगलवार को शुरुआती कारोबार में इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली। दो दिनों की सुस्ती के बाद निवेशकों को सस्ते वैल्यूएशन पर खरीदारी का मौका मिल गया। SBI, कोटक महिंद्रा और ICICI बैंक के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इससे जाहिर होता है कि बैंकिंग सेक्टर मल्होत्रा की नियुक्ति से खुश है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, ₹चीन के शीर्ष नेताओं ने संकेत ने दिया है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए अगले साल और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।₹ इससे एशियाई बाजारों में तेजी आई, जिसका फायदा भारतीय स्टॉक मार्केट को भी मिला है। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.29 प्रतिशत गिरकर 71.93 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 724.27 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,648.07 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। सोमवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 200.66 अंक गिरकर 81,508.46 पर बंद हुआ था। वहीं, एनएसई निफ्टी 58.80 अंक गिरकर 24,619 के स्तर पर आ गया था।

रुपये का क्या है हाल?

मंगलवार को सुबह के कारोबार में रुपया अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर से उबरकर 8 पैसे बढ़कर 84.78 प्रति डॉलर (Rupee Performance) पर पहुंच गया। इसे ताजा विदेशी फंड प्रवाह और घरेलू इक्विटी में सकारात्मक रुझान का सहारा मिला। सरकार ने सोमवार को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि शक्तिकांत दास के जाने से अनिश्चितता आई है, क्योंकि उनके कार्यकाल में ऐसी नीतियां अपनाई गई थीं, जिनसे रुपये में बड़ी गिरावट नहीं आई। सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के एमडी अमित पबारी ने कहा, "साथ ही, राजस्व संबंधी चिंताओं पर आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले संजय मल्होत्रा के रुख ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं।"

अपने बैंक खाते से पैसा निकालने पर भी देना पड़ेगा टैक्स, जाने सालभर में कितनी रकम निकाल सकते हैं

परिवहन विशेष न्यूज

हम आज आपको बताने जा रहे हैं बैंक अकाउंट से पैसे निकालने से पहले आपको कौन से आयकर नियम और बैंकिंग शुल्क आपको पता होने चाहिए। अपने पैसे निकालने से पहले इन जरूरी जानकारियों को जानना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

अगर आप यह सोचते हैं कि अपने बैंक अकाउंट में जमा पैसे को बिना किसी टेंशन के कभी भी निकाल सकते हैं तो आपके लिए यह जानकारी अति आवश्यक है। अपनी बैंक ट्रांजेक्शन की योजना बनाते समय आपको यह पता होना जरूरी है कि कितनी रकम बिना टैक्स चुकाए निकाली जा सकती है। आज एटीएम से ही नहीं बल्कि बैंक से कैश निकालने पर भी एक तय सीमा के बाद टैक्स और शुल्क लगाने का नियम है।

यदि आप अधिक बार पैसे निकालते हैं तो इस पर शुल्क और टैक्स दोनों लग सकते हैं। इस लेख में हम आपको बैंक ट्रांजेक्शन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जो आपकी मदद करेगी और आपको अनावश्यक खर्चे से बचा देगी।

अकाउंट से कितना कैश निकाल सकते हैं?
कई लोगों को लगता है की वह अपने बैंक अकाउंट से जितना चाहें उतना कैश निकाल सकते हैं लेकिन यह सोच गलत है। आयकर अधिनियम की धारा 194एन के तहत, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक रकम निकालते हैं तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने पिछले 3 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आई टीआर) नहीं भरा है। ऐसे लोग यदि 20 लाख रुपये से अधिक की रकम किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से निकालते हैं तो उन पर 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस कटेगा।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए राहत
अगर आपने समय-समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरा है तो आपको इस नियम से राहत मिलती है। ऐसे कस्टमर बिना किसी टीडीएस के बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक से एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक निकाल सकते हैं। यह नियम आईटीआर भरने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से राहतकारी है, क्योंकि उन्हें भारी टैक्स चुकाने से बचने का मौका मिलता है।

टीडीएस कितना देना पड़ेगा? यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कैश निकालते हैं, तो 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस कटेगा। लेकिन यदि आपने पिछले तीन साल से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है तो आपको 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 प्रतिशत टीडीएस देना पड़ेगा। इस तरह से आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी कैश ट्रांजेक्शन लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही पैसा निकालें जिससे अप्रत्याशित टैक्स के भुगतान से बच सकें।

एटीएम ट्रांजेक्शन पर पहले से ही चार्ज है अब तक आप जानते थे कि एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा बार रुपये निकालने पर बैंक शुल्क लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक जनवरी, 2022 से एटीएम से कैश निकालने पर सर्विस चार्ज बढ़ा दिया था? अब यदि आप बैंक द्वारा निर्धारित ट्रांजेक्शन लिमिट से अधिक बार एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो आपको 21 रुपये चार्ज देना पड़ता है। इससे पहले यह शुल्क 20 रुपये था। अधिकांश बैंक अपने एटीएम से हर महीने पांच ट्रांजेक्शन फ्री देते हैं, जबकि दूसरे बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजेक्शन मुफ्त होते हैं। मेट्रो शहरों में, अपने बैंक के एटीएम से भी आपको केवल तीन बार फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं।

जरुरी सवाल जो उठते हैं

1. क्या आईटीआर भरने से मुझे पूरी तरह से टीडीएस से राहत मिल जाती है? जी हां, आईटीआर भरने वाले लोग एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक बिना किसी टीडीएस के कैश निकाल सकते हैं।

2. क्या 20 लाख रुपये से अधिक निकालने पर हर बार टीडीएस देना पड़ता है? नहीं, टीडीएस तभी लागू होता है जब आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की रकम निकालते हैं और आपने पिछले 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है।

3. क्या एटीएम से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर शुल्क लगता है? हां, एटीएम से तय सीमा से अधिक ट्रांजेक्शन करने पर बैंक 21 रुपये का शुल्क लेते हैं।

साथ ही आपको एटीएम से कैश निकालने के नियम भी बता रहे है, जो आपके जानने योग्य है

देशभर में एटीएम से नकद वापसी (कैश रिट्रैक्शन) की सुविधा फिर से शुरू की जा रही है। यह सुविधा ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने और ठगी रोकने के उद्देश्य से लागू की गई है। ग्राहकों को अपनी राशि तुरंत ग्रहण करने की सलाह दी जाती है, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।

देशभर में एटीएम से नकद वापसी (कैश रिट्रैक्शन) की सुविधा को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और बैंकों ने यह कदम एटीएम से संबंधित धोखाधड़ी रोकने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया है। नए नियमों के तहत, जब कोई ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर पैसे ग्रहण नहीं करता, तो एटीएम द्वारा उस राशि को वापस खींच लिया जाएगा। यह कदम ठगी और सुरक्षा जोखिम को कम करने में मदद करेगा, साथ ही एटीएम के इस्तेमाल में आने वाली परेशानियों को भी दूर करेगा।

कैश रिट्रैक्शन सुविधा का कार्यप्रणाली कैश रिट्रैक्शन सुविधा का उद्देश्य ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना और एटीएम मशीनों को सुरक्षित बनाना है। पहले, अगर ग्राहक एटीएम से पैसे निकालते थे और कुछ कारणों से पैसे नहीं ले पाते थे, तो उस राशि को कोई और व्यक्ति निकाल सकता था। अब नए नियमों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने के बाद उसे समय सीमा के भीतर ग्रहण नहीं करता, तो मशीन उस राशि को वापस खींच लेगी।

यह सुविधा एटीएम की सुरक्षा में सुधार करने के साथ-साथ बैंकिंग धोखाधड़ी को भी रोकने में मदद करेगी। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एटीएम से पैसा निकालने के बाद उसे छोड़ देता है, तो बैंक उसे वापस ले सकेगा। इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति उस पैसे का गलत तरीके से फायदा नहीं उठा सकेगा।

कैश रिट्रैक्शन के फायदे

1. ग्राहकों की सुरक्षा में वृद्धि: कैश रिट्रैक्शन की सुविधा से ग्राहकों को सुरक्षा का अहसास होगा। अगर एटीएम से निकाली गई राशि छोड़ दी जाती है तो उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाने से रोका जा सकेगा।

2. धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी: अक्सर एटीएम से पैसे निकालने के बाद कई बार पैसे एटीएम मशीन के पास छोड़ दिए जाते हैं, और ठग उस पैसे को उठा लेते हैं। इस सुविधा के बाद एटीएम निर्धारित समय में वापसी कर देगा, जिससे धोखाधड़ी की घटनाएं कम होंगी।

3. ऑपरेशन में पारदर्शिता: इस कदम से एटीएम के ऑपरेशन में पारदर्शिता बढ़ेगी, और ग्राहकों को यह पता चलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है, और एटीएम से पैसे निकालने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी।

कैश रिट्रैक्शन सुविधा का उपयोग कैसे करें?
एटीएम से पैसे निकालते वक्त ध्यान रखें: जब आप एटीएम से पैसे निकालें, तो सुनिश्चित करें कि आप तुरंत उन्हें ग्रहण कर लें।

समय सीमा का पालन करें: अगर आप पैसे निकालने के बाद कुछ कारणवश उन्हें नहीं ले पाते हैं, तो ध्यान रखें कि एटीएम मशीन में निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि लौट जाएगी।

सुरक्षा को प्राथमिकता दें: हमेशा एटीएम से पैसे निकालते वक्त अपने चारों ओर ध्यान रखें, और सुनिश्चित करें कि कोई आपके पास से पैसे न उठा सके।

सर्वकालिक, सार्वभौमिक, शाश्वत एवं श्रेष्ठ मार्गदर्शक श्रीमद्भगवद्गीता

(विवेक रंजन श्रीवास्तव -विनायक फीचर्स)

श्रीमद्भगवतगीता अध्यात्म ज्ञान और जीवन शैली सिखाने वाला विश्वविख्यात अनुपम ग्रंथ है। गीता के अध्ययन और मनन से व्यक्ति आत्म शांति का अनुभव कर सकता है। जीवन को सुखी बना सकता है।

योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्ठापूर्वक कर्म करके अपने जीवन को सफल करने का जो महत्वपूर्ण उपदेश 'कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन' दिया। यह जीवन के मूल को समझने और व्यवहार करने का शाश्वत सूत्र है। रणभूमि में अर्जुन के हताश मन में नई स्फूर्ति और ओज भरने को कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इस बहाने सारी मनुष्य जाति का जीवन-समर को सही रीति से जीतने का अमर मंत्र गीता में ही है। इस तरह गीता हिन्दू धर्म विशेष की नहीं वैश्विक मूल्य की कृति है इसीलिए दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में गीता प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके भाष्य और विवेचन निरन्तर विद्वानों द्वारा किए जाते हैं। गीता पर प्रवचन लोग रुचि से सुनते हैं।

द्वापर युग के समापन तथा कलियुग आगमन के समय आज से कोई पांच हजार वर्ष पूर्व कुरूक्षेत्र के रणांगण में उस समय गीता कही गई, जब महाभारत युद्ध आरंभ होने के समस्त संकेत योद्धाओं को मिल चुके थे। श्रीमद्भगवदगीता के प्रथम अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। यथा युद्ध के वाद्यों का बजना, समस्त प्रकार के नादों का गूंजना, यहाँ तक कि तत्कालीन (द्वापर युग के) महानायक भगवान श्री कृष्ण के शंख ₹पांचजन्य₹ का उद्‌घोष, यह सब युद्धारंभ के स्पष्ट संकेत थे।

आज भी दुनिया कुछ वैसे ही कोलाहल, असमंजस और किंकर्तव्यविमूढ़ स्थिति में है। मानव मन जीवन रण में छोटी बड़ी परिस्थितियों में सदैव इसी तरह की उहापोह में डोलता रहता है इसलिए गीता सर्वकालिक सर्वप्रासंगिक बनी हुई है।

श्रीमद्भगवद्गीता का भाष्य ही वास्तव में "महाभारत" है। गीता को स्पष्टतः समझने के लिये गीता को महाभारत के प्रसंगों में पढ़ना और हृदयंगम करना आवश्यक है। महाभारत तो विश्व का इतिहास ही है। ऐतिहासिक एवं तत्कालीन घटित घटनाओं के संदर्भ मे झांककर ही श्रीमद्भगवद्गीता के विविध दार्शनिक-आध्यात्मिक व धार्मिक पक्षों को व्यवस्थित ढंग से समझा जा सकता है।

अनेक विद्वानों के गीता के हिंदी अनुवाद के क्रम में हिंदी काव्य में छंद बद्ध सरस पदों में प्रो. चित्र भूषण श्रीवास्तव विदग्ध ने भी इसका पद्यानुवाद किया है जिसे पढ़कर गीता को सरलता से समझा व आत्मसात किया जा सकता है। (विनायक फीचर्स)

सरायकेला में फंदा डालकर प्रताड़ित युवक की आत्महत्या

परिवहन विशेष न्यूज

सरायकेला: झारखंड को ओडिशा तरफ जानेवाली सरायकेला निकट खरखाई नदी के मांजना घाट में बने पुल के रेलिंग में मंगलवार सुबह गला में फंदा लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जिसके सुबह घूमने जा रहे बाद लोगों का हूजूम बढ़ता देख पुलिस को खबर की गयी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाना ले गयी।

घटना मंगलवार सुबह 5:45 के आसपास की है। मृतक की पहचान सरायकेला तेलीसाही निवासी रंजीत पति के रूप में की गई। घटना के संबंध में स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुबह दुकान के आसपास झाड़ू लगाया। इसके बाद प्रतिदिन की भांति वह खरकई नदी के मांझना घाट की तरफ मॉर्निंग वॉक के लिये निकल गया। कुछ देर बाद उनके आत्महत्या की सूचना मिली। मृतक के दो नबालिक बच्चे है। बताया गया वह कुछ दिनों से काफी तनाव में रहता था लेकिन इस तरह से कदम उठा लेगा इस पर किसी को भी भरोसा नहीं था। इधर कई लोगों ने उसे 5:30 के आसपास बाजार क्षेत्र में घूमते हुए देखने की बात कही है।

सरायकेला के थाना प्रभारी सतीश वर्णवाल ने कहा कि मृतक के परिजन द्वारा उसे उनके संबंधियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने की जानकारी लिख कर दी गयी है। अब पुलिस तफ्तीश में जुटी टी है।

अब रिश्वत के बल पर मनचाही पोस्टिंग नहीं करा पा रहे कानपुर के भ्रष्ट पुलिस वाले, चर्चा में सीपी

- ट्रांसफर माफिया दद्दा के जरिए कानपुर में पहले खुलेआम होती थी थानों, चौकियों की नीलामी, करोड़ों ले गए कई भ्रष्ट अधिकारी
- थानों और चौकियों को अपना घर मकान मान उस समय थानेदार रूपी किराएदारों से पगड़ी के साथ मासिक किराया भी किया जाता था वसूल

सुनील बाजपेयी

कानपुर। यहां पहले की तरह रिश्वत के बल पर मनचाही पोस्टिंग में सफलता नहीं मिलने से कतिपय भ्रष्ट पुलिस वाले आजकल बहुत परेशान, हताश और निराश बताये जाते हैं। मतलब अब उनका रिश्वत के बल पर मनचाही पोस्टिंग कराने का सपना किसी भी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी असली वजह है, यहां के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की कर्तव्य के प्रति परिश्रम पूर्ण प्रगाढ़ निष्ठा और उनकी बेहद ईमानदारी। यही वजह है कि यहां के सभी 52 थानों में ऐसा कोई थाना नहीं है, जहां किसी भी थानेदार को पूर्व की तरह रिश्वत के बल पर पोस्टिंग कराने में सफलता मिली हो और फिर उसी के बदले उसे विभिन्न हड़कंडों से दस गुना पैदा करने का मौका मिला हो या मिल रहा हो।

इसी आधार पर भरोसेमंद का दावा है कि अगर भ्रष्ट थानेदारों का बस चले तो वे किसी ऐसे भ्रष्ट्र को कानपुर का पुलिस कमिश्नर बनवा दें, जो मनचाही पोस्टिंग करने की अपनी कीमत ले और बदले में उन्हें भी कमाने का मौका दे।

वैसे कानपुर को आज भी वह समय याद है, जब रिश्वतखोरी के रूप में अधिक से अधिक कमाई के लिए अनेकानेक भ्रष्ट पुलिसकर्मी उस समय बहुत खुश हुआ करते थे, जब वे ले देकर अपनी मनचाही पोस्टिंग कराने में सफल रहते थे। मतलब अधिकांश भ्रष्ट पुलिस वालों की महाभ्रष्ट माने उन अधिकारियों से ही ज्यादा पटती रही है, जो उस समय 50 हजार से लेकर चार - पांच लाख में थानों और पुलिस चौकियों आदि को भी सरेआम नीलाम करने के साथ ही सुरा और सुन्दरी के सेवन के लिए भी कुख्यात माने जाते रहे हैं।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक कानपुर में पोस्टिंग के उस कालखंड में कुछ को छोड़ कर बाकी नियुक्त रहे कई भ्रष्ट आई पी एस अधिकारी कुख्यात ट्रांसफर माफिया लल्ला उर्फ दल्ला उर्फ दद्दा के माध्यम से भी थानाध्यक्ष बनाने के लिए कम से कम तीन से पांच लाख और चौकी के लिए पचास हजार खुले आम लेते थे, यही नहीं सिपाहियों के तबादले का रेट भी पंद्रह से लेकर बीस हजार तक कर रखा गया था। मतलब उस समय नियुक्ति के मामले में थानों और चौकियों की हालत वही थी, जो दुकान - मकान मालिक और किरायेदार के बीच होती है। यानी थानों और चौकियों को अपना मकान और दुकान मानने वाले यहां ऐसे भी कई पुलिस अधिकारी पोस्ट रहे, जो उस समय कुख्यात ट्रांसफर माफिया लल्ला उर्फ दल्ला उर्फ दद्दा आदि के माध्यम से थानेदार रुपी किरायेदारों से लाखों की पगड़ी के साथ हर माह लाखों रुपये उसका किराया भी वसूलते थे और जो भी थानेदार अदा करने में अक्षम रहता था, उससे थानों और चौकियों रुपी मकान को तत्काल खाली कराकर उसे दे दिया जाता था, जो हर माह बढ़ा हुआ किराया देने में सक्षम होता था।

जानकार सूत्रों की नजर में अब जहां तक वर्तमान

परिस्थितियों का सवाल है। अगर कोई भी पुलिस वाला रिश्वत के बल पर मनचाही कमाऊ पोस्टिंग हासिल करना चाहता है तो उसकी यह तमन्ना तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक यहां पुलिस कमिश्नर के रूप में कानपुर की कमान कानून और शांति व्यवस्था के पक्ष में अपराधियों के खिलाफ सफल मोर्चा खोले और हर स्तर की अनुचित सिफारिशों को जूते की नोक पर मारने के लिए भी चर्चित निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यशैली के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस अखिल कुमार के हाथ में है। इसी के साथ यह भी जान लेना चाहिए कि पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से समझौता आजतक नहीं किया। और ना ही कभी करेंगे। वह एक दिन भी यहां रहें अथवा ना रहें। मतलब अब वह समय चला गया, जब मुंह मांगी कीमत जमा करने के बदले मनचाही नियुक्ति वाली आदेश पर्ची मिल जाया करती थी। थाने के लिए भी और चौकी के लिए भी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आजकल पुलिस कमिश्नर के रूप में कानपुर की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार की मंशा पर हर दृष्टिकोण से खरे उतरने वाले बेहद ईमानदार और कर्तव्य के प्रति बेहद निष्ठावान आई पी एस अखिल कुमार के हाथ में है। और यह वही वरिष्ठ आईपीएस अखिल कुमार हैं, जिनकी निष्पक्ष, पारदर्शी और कठोर परिश्रम पूर्ण ईमानदार कार्यशैली तथा व्यवहार से सदैव यही प्रमाणित हुआ है कि अच्छे कार्यों के लिए हर स्थिति में और हर तरह से साथ देते हुए मातहतों का मनोबल बढ़ाना, कार्य सरकार के प्रति लापरवाही, जानबूझ कर किए गये अपराध, गल्ती पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना और भ्रष्ट पुलिस वालों को सबक सिखा कर ही चैन की सांस लेना भी उनके जुझारू स्वभाव का प्रमुख हिस्सा है, जिसकी पुष्टि निर्दोष फंसे नहीं और अपराधी बचे नहीं जैसी विचारधारा के अनुरूप अब तक के उत्कृष्ट सराहनीय सेवा कार्यकाल में मानवीय दृष्टिकोण वाले बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को अति सुगम बनाने के साथ ही ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अब तक हजारों की संख्या में लग चुके सीसीटीवी कमरों के जरिए छोटी बड़ी हर घटना के अपराधियों को अति शीघ्र पकड़ने और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को भी भरपूर सबक सिखाने से भी होती है। भरोसे मंद सूत्रों की नजर में यह बात दीगर है कि अगर यूपी में भ्रष्टाचार को काफी हद तक खत्म करने में पूर्ण रूप से सफल योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो सफेदपोश माफिया अपराधियों और भ्रष्ट्र पुलिस वालों का इरादा अवश्य ही पूरा हो गया होता। मतलब रिश्वत के बल पर मनचाही पोस्टिंग में बाधक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ वरिष्ठ आईपीएस एडीजी अखिल कुमार की जगह अब तक कोई महाभ्रष्ट्र कुंडली मारकर कानपुर में बैठ भी चुका होता।

वायु विहार सड़क संघर्ष समिति ने गंगाजल के लिए मुख्यमंत्री के नाम मंडलायुक्त को दिया ज्ञापन

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। वायु विहार से बाबू जी चौराहे तक 100 फुटा वायु विहार मार्ग एवं उसके आस पास पथौली तक स्थित पचासों कॉलोनियों में गंगा जल की मांग के लिए मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी को ज्ञापन सौंपा गया।

वायु विहार सड़क संघर्ष समिति का कहना है कि इस क्षेत्र में खारे पानी की समस्या वर्षों से बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खारे पानी से निजात दिलाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना चलाई, जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार तक मीठा पानी पहुंचे। जनपद आगरा में इस योजना के तहत गंगा जल की लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। वायु विहार मार्ग और पथौली के क्षेत्र में सैकड़ों कॉलोनियां बसी हुई हैं जिनसे बहुत सारी एडीए अप्रूव हैं। इस क्षेत्र की कॉलोनियों में गंगाजल की लाइन बिछाने का कार्य नहीं हो रहा। कॉलोनियों को छोड़कर हर घर तक पानी पहुंचाने का कार्य हो रहा है जबकि कलवारी, पथौली ग्राम पंचायत के अंतर्गत यह अधिकांश क्षेत्र आता है और कुछ क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत भी आता है लेकिन न तो नगर निगम इस क्षेत्र की कॉलोनियों में गंगाजल का पानी पहुंचा रहा। इस प्रकार से वायु विहार मार्ग, पथौली तक के आस पास के कॉलोनीवासियों ने गंगाजल के लिए वायु विहार सड़क संघर्ष समिति के अंतर्गत ज्ञापन दिया है।

वहीं, संघर्ष समिति के सचिव विजयपाल नरवार का कहना है कि गंगाजल के लिए क्षेत्र की 50 से अधिक कॉलोनियों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मंडलायुक्त आगरा को 1800 से ज्यादा परिवारों के हस्ताक्षरयुक्त 90 पेज का ज्ञापन दिया गया है। गंगाजल के लिए सफल होने तक समिति लगातार संघर्ष करती रहेगी। ज्ञापन देने वालों में संघर्ष समिति सचिव विजयपाल नरवार के साथ सत्यवीर सिंह, अभिषेक जैन, कुशाल सिंह, जग्गी प्रजापति, रविन्द्र वर्मा आदि शामिल रहे।

सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा की लापरवाही

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान अग्नि रोकथाम और आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में ज्ञान फैलाने में मदद कर सकते हैं। अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने वाले अस्पतालों को सब्सिडी या अनुदान जैसे प्रोत्साहन प्रदान करने से बेहतर कार्यान्वयन को बढ़ावा मिल सकता है। झांसी में अस्पताल में लगी दुखद आग सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा प्रवर्तन में चल रही खामियों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। जापान जैसे देशों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, जहाँ आग से होने वाली मौतों की दर सबसे कम है, एक मार्गदर्शक प्रकाश हो सकता है। सरकार को सुरक्षित सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने, विनियमन को बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

-- डॉ० सत्यवान सौरभ

उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अस्पताल में लगी दुखद आग, जिसमें 11 नवजात शिशुओं की जान चली गई, भारत के सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा उपायों की विफलता को उजागर करती है। राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) और अग्नि सुरक्षा और रोकथाम नियमों के बावजूद, कई अस्पताल इन विनियमों का पालन नहीं करते हैं। यह बेहतर अग्नि सुरक्षा प्रवर्तन और भविष्य में जानमाल के नुक़सान को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे में महत्त्वपूर्ण उन्नयन की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देता है। सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ अग्नि सुरक्षा कार्यान्वयन में त्रुटिपूर्ण हैं। भ्रष्टाचार और अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में उचित निगरानी की कमी के कारण कई अस्पताल निर्धारित अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, कई अस्पताल विनियामक जाँच को दरकिनार कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप असुरक्षित संरचनाएँ बन जाती हैं जो अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती हैं।

अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और योजना: अनुचित योजना और घटिया निर्माण के कारण अक्सर सार्वजनिक संस्थानों, विशेषकर अस्पतालों में आग का ख़तरा पैदा होता है। कोलकाता एएमआरआई अस्पताल में आग लगने की घटना (2011) ने संरचनात्मक योजना में गंभीर खामियों को उजागर किया, जैसे कि अवरुद्ध भागने के रास्ते और अपर्याप्त अग्नि निकास, जिसने बड़ी संख्या में मौतों में योगदान दिया। जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी जैसे चिकित्सा कर्मचारी और अग्नि सुरक्षा कर्मियों को अक्सर आग की रोकथाम, आपातकालीन निकासी या अग्निशमन तकनीकों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। मुंबई (2020) में एक कोविड -19 सुविधा में आग लगने से तैयारियों की कमी का पता चला, अस्पताल के कर्मचारी अपर्याप्त प्रशिक्षण और जागरूकता के कारण आग की आपात स्थिति को संभालने में असमर्थ थे। कई अस्पताल, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने या पर्याप्त अग्निशमन उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी रखते राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में 2022 में 7, 500 से अधिक आग दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 7, 435 मौतें हुईं, जो खराब प्रवर्तन के गंभीर परिणामों को दर्शाता है।

कई अस्पतालों में आग के खतरों से बचाव के लिए समर्पित निकासी मार्ग, अग्निरोधी सामग्री और अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अभाव है। उपहार सिनेमा अग्नि (1997), जिसमें 59 लोग मारे गए थे, अपर्याप्त निकास बिंदुओं के कारण और भी गंभीर हो गई थी, जो एनबीसी और एनडीएमए दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित मज़बूत निकासी योजना की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अग्नि सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन में भिन्नताएँ क्षेत्रीय असमानताएँ पैदा करती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के उपाय निगरानी और विनियमन को मज़बूत करना है। अग्नि सुरक्षा मानदंडों की मज़बूत निगरानी सुनिश्चित करना और सभी अस्पतालों के लिए अग्नि सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य बनाना अनुपालन में सुधार कर सकता है। सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के लिए एनडीएमए के दिशानिर्देशों को नियमित निरीक्षण और गैर-अनुपालन के लिए दंड के साथ और अधिक सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अस्पतालों को आधुनिक अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, जिसमें फायर अलार्म, स्प्रिंकलर और अग्नि शमन प्रणाली शामिल हैं।

दिल्ली के एम्स में अग्नि सुरक्षा उपाय, जिसमें उन्नत अग्नि पहचान और दमन प्रणाली शामिल हैं, अन्य अस्पतालों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। आपातकालीन प्रक्रियाओं पर अस्पताल के कर्मचारियों के लिए नियमित अग्नि सुरक्षा अभ्यास और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं। एनडीआरएफ द्वारा शुरू किए गए अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को किसी संकट के दौरान कर्मचारियों की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए सभी अस्पतालों में दोहराया जा सकता है। सरकारों और अस्पताल अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे और नियमित रखरखाव के लिए अधिक धन आवंटित करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) नए अस्पताल परियोजनाओं के लिए अपने वित्त पोषण प्रस्तावों के अनिवार्य हिस्से के रूप में अग्नि सुरक्षा को शामिल कर सकता है, विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में। अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने से बेहतर सतर्कता और सुरक्षा मानकों के पालन को बढ़ावा मिल सकता है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान अग्नि रोकथाम और आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में ज्ञान फैलाने में मदद कर सकते हैं। अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने वाले अस्पतालों को सब्सिडी या अनुदान जैसे प्रोत्साहन प्रदान करने से बेहतर कार्यान्वयन को बढ़ावा मिल सकता है। झांसी में अस्पताल में लगी दुखद आग सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा प्रवर्तन में चल रही खामियों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। जापान जैसे देशों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, जहाँ आग से होने वाली मौतों की दर सबसे कम है, एक मार्गदर्शक प्रकाश हो सकता है। सरकार को सुरक्षित सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने, विनियमन को बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

ओडिशा के इन दो जिलों में बनेंगे रेलवे फ्लाईओवर, 509 करोड़ रुपये की लागत से रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: रेल मंत्रालय ने कटक और रायगड़ा जिलों में दो प्रमुख रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 509 करोड़ ई मंजूर किए हैं। रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने ओडिशा में इस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की जानकारी दी है। इससे रेलवे लाइनों पर ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी। रेलवे ने अपनी व्यापक ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर योजना के हिस्से के रूप में दो फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य रेल यातायात में सुधार करना और प्रमुख रेलवे लाइनों पर भीड़ को कम करना है। अपने हालिया ओडिशा दौरे के दौरान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में दो रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने का भी उल्लेख किया।

कटक जिले में 10.89 किमी लंबा रेलवे फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस परियोजना में कटक जिले में राजथगढ़, राधाकिशोरपुर और मिशपुर रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाले 10.89 किलोमीटर रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है। यह बुनियादी ढांचा क्रॉस ट्रैफिक की समस्या को खत्म कर देगा और एक साथ ट्रेन संचालन की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 268.92 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। इसी तरह रायगड़ा जिले में 5.50 किमी लंबा रेलवे फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए 239.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। रायगड़ा जिले के सिंगापुर रोड स्टेशन पर 5.50 किमी लंबा रेलवे फ्लाईओवर बनाया जाएगा। जिससे रायपुर-बिजयनगरम रेलवे लाइन पर ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। सिंगापुर रोड स्टेशन से सटे स्टेशनों पर नॉन-स्टॉप ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है। क्रॉस ट्रैफिक के कारण होने वाली देरी से भी बचा जा सकेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023